page 1 and 8 jan 29_page 1 Mar 25 final ds.qxd 1/29/2026 1:40 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 अवैध खनन में लिप्त 4 डंपर जब्त

5 जोस बटलर बने 400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी

8 खजूर की खेती- जलवायु, किस्में, प्रबंधन, देखभाल और पैदावार

मौसम जम्मू — न्यूनतम 9 — अधिकतम 14

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-26 | जम्मू तवी, वीरवार 29 जनवरी, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 की मौत

मुंबई, 28 जनवरी। पुणे जिले के बारामती के पास बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुआ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हवा में अस्थिर दिखाई दे रहा था और जमीन से टकराते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया, बारामती रनवे से महज 100 फीट की दूरी पर हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान अस्थिर था और टकराते ही आग का गोला बन गया, यह जानकारी एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा? 1. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान आग की लपटों में घिर गया, जिसके बाद एक के बाद एक चार से पांच विस्फोट हुए।

अधिकारियों के अनुसार, सुबह 8:50 बजे बारामती के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 66 वर्षीय पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। 2 . महिला प्रत्यक्षदर्शी ने एक समाचार चैनल को बताया कि उसने सुबह विमान को बारामती हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते देखा था। उसने कहा, फ़विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया, वह थोड़ा अस्थिर लग रहा था। जैसे ही वह उतरने के लिए रनवे के करीब पहुंचा, वह जोर से जमीन से टकराया और उसमें विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज हमारे घर तक सुनाई दी।

उसने आगे बताया कि विस्फोट के बाद विमान के कई हिस्से हवा में उछलकर उसके घर के पास गिरे। उसने कहा, नीचे आने से पहले विमान एक तरफ झुक गया था। हमने अपनी आंखों से धमाका देखा, वह बहुत डरावना था। 3. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नीचे उतरते समय विमान अपना नियंत्रण खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने संवाददाताओं से कहा, फ़जिस तरह से विमान नीचे आ रहा था, हमें लग गया था कि यह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। वह रनवे से करीब 100 फीट ऊपर था। जैसे ही हम उसकी ओर भागे, हमने लपटें देखीं, जिसके बाद लगातार चार-पांच धमाके हुए। धमाकों की वजह से हम विमान के पास नहीं जा सके।उसने भावुक होते हुए कहा, आग बहुत भीषण थी। बाद में हमें पता चला कि विमान में अजीत पवार सवार थे। यह हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे पर दुख जताया

जम्मू, 28 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराष्ट्र के बारामती में हुए बड़े विमान हादसे पर दुख जाहिर किया है।

उपराज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अजीत पवार के असमय निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा और दुख हुआ है। वह एक बहुत सम्मानित नेता थे, जो लोगों की भलाई के लिए समर्पित थे और जिन्होंने महाराष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा की उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं है।

भारत ग्लोबल साउथ और दुनिया के बीच प्रमुख एविएशन गेटवे के रूप में उभर रहा : मोदी

नई दिल्ली, 28 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत तेजी से ग्लोबल साउथ और दुनिया के बीच एक प्रमुख एविएशन गेटवे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधारों के कारण भारत आज निवेशकों, निर्माताओं और नवाचारकर्ताओं के लिए बड़े अवसरों का केंद्र बन गया है।

प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र आज बड़े पैमाने, नीति स्थिरता और तकनीकी महत्वाकांक्षा का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे देश हैं जहां विमानन उद्योग के लिए इतनी व्यापक संभावनाएं मौजूद हों। उन्होंने वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे भारत की विकास यात्रा में दीर्घकालिक भागीदार बनें और वैश्विक विमानन क्षेत्र की प्रगति में योगदान दें।

मोदी ने कहा कि भारत न केवल विभिन्न शहरों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है, बल्कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए शहरों को बंदरगाहों और बाजारों से भी जोड़ रहा है। भारत की एविएशन विजन केवल यात्री परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि एयर कार्गो पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्गो मूवमेंट को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए आवश्यक सभी नियामकीय सुधार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्गो प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जबकि ऑफ-एयरपोर्ट प्रोसेसिंग व्यवस्थाएं हवाई अड्डों पर दबाव कम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं, जिससे कार्गो हैंडलिंग में तेजी आएगी और भविष्य में डिलीवरी समय तथा लॉजिस्टिक्स लागत दोनों में कमी होगी। भारत एक प्रमुख और प्रतिस्पर्धी ट्रांस-शिपमेंट हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेशकों से वेयरहाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विंग्स इंडिया जैसे मंच विमानन उद्योग के सभी हितधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों और निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि विमानन उद्योग का अगला युग आकांक्षाओं से भरा हुआ है और भारत इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विमान निर्माण, पायलट प्रशिक्षण, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी और एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे क्षेत्रों में मौजूद विशाल अवसरों को रेखांकित किया।

पिछले एक दशक में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। कभी हवाई यात्रा कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी लेकिन आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। यात्री यातायात में तेज वृद्धि हुई है और भारतीय एयरलाइंस ने हाल के वर्षों में 1,500 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि सरकार की दीर्घकालिक सोच और 'हवाई यात्रा को समावेशी बनाने' के दृष्टिकोण का परिणाम है। वर्ष 2014 में देश में जहां केवल 70 हवाई अड्डे थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। यानी एक दशक में दोगुने से भी ज्यादा हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक एयरोड्रोम सक्रिय किए गए हैं और साथ ही उड़ान योजना शुरू की गई, जिससे किफायती हवाई यात्रा संभव हो सकी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले वाहन प्रवेश, पार्किंग प्रतिबंध जारी

जम्मू, 28 जनवरी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 5वें सत्र से पहले, सरकार ने सिविल सचिवालय, जम्मू में और उसके आसपास वाहनों के प्रवेश और पार्किंग को विनियमित करने के लिए एक सलाह जारी की है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों सहित कर्मचारियों के किसी भी निजी वाहन को सिविल सचिवालय परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।

सिविल सचिवालय के कर्मचारियों के निजी वाहनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्माणाधीन विधानसभा परिसर में उपलब्ध निर्दिष्ट स्थान पर पार्क किया जाएगा जबकि एस्कॉर्ट और मीडिया वाहनों को इन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन आंदोलन और पार्किंग को विनियमित करने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), नागरिक सचिवालय के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है और प्रशासनिक सचिवों को सभी कर्मचारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

आतंकवादियों द्वारा छिपाए गए हथियार और गोला-बारूद बरामद

कुपवाड़ा, 28 जनवरी । बुधवार को सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक वन क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा छिपाए गए हथियार और गोला-बारूद बरामद किए।

अधिकारियों ने बताया कि कर्नाह तहसील के रति तारी वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान चार पिस्तौल, सात मैगज़ीन, तीन एके मैगज़ीन और 308 एके-47 राउंड बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है।

भूस्खलन से 87 पशु मरे

जम्मू,, 28 जनवरी । किश्तवाड़ के हस्ती क्षेत्र में एक भूस्खलन में सचिन सिंह के अस्थायी गौशाला पूरी तरह दब गई जिसमें उनके 87 पालतू पशु जिनमें 20 भेड़, 50 बकरियां और 17 बच्चे शामिल थे की मौत हो गई। सचिन सिंह ने बताया कि रात लगभग 3 बजे अजीब आवाजें सुनकर बाहर गए थे लेकिन अंधेरे और परिस्थितियों के कारण कुछ समझ नहीं पाए। सुबह जब वह पशुओं को खिलाने गए तो देखा कि गौशाला पूरी तरह मलबे में बदल चुकी है। इस हादसे में उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के बाद नायब तहसीलदार, पटवारी, किश्तवाड़ पुलिस और शीप हसबैंड्री विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। रेड क्रॉस किश्तवाड़ की टीम ने भी स्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवार को समय पर सहायता देने का आश्वासन दिया।

पीएचडीसीसीआई ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, उद्योग व पर्यटन के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज की मांग, जम्मू क्षेत्र पर फोकस

जम्मू, 28 जनवरी । पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) जम्मू क्षेत्र के चेयरमैन राकेश वज़ीर ने प्री-बजट बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के लिए विशेष पुनरुद्धार पैकेज की मांग की। ज्ञापन में विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और पर्यटन की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई गई और इनके संरक्षण व पुनर्जीवन के लिए ठोस सुझाव रखे गए। पीएचडीसीसीआई ने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम को सितंबर 2024 के बाद भी जारी रखने तथा इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने की मांग की। साथ ही होटलों के नवीनीकरण, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के उन्नयन और औद्योगिक पैकेज 2017 की तर्ज पर विस्तार लाभ बहाल करने पर जोर दिया गया। पर्यटन आधारित विकास को अहम बताते हुए चैंबर ने होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बोर्डिंग स्कूल और हॉस्पिटैलिटी संस्थानों में निवेश बढ़ाने की अपील की, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिल सके। होटल उद्योग के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति और औद्योगिक बिजली दरों का लाभ विनिर्माण इकाइयों के समान देने की मांग भी उठाई गई।ज्ञापन में आटा मिल उद्योग की समस्याओं का उल्लेख करते हुए बताया गया कि पंजाब द्वारा गेहूं पर लगाए गए 6 प्रतिशत मंडी शुल्क के कारण जम्मू-कश्मीर की मिलें प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष वैष्णो देवी आने वाले लगभग एक करोड़ श्रद्धालुओं को प्रदेश के अन्य पर्यटन व तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित करने के सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्येक मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

विधायक जम्मू ईस्ट, डिव कमिश्नर ने तवी बोटिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया

जम्मू, 28 जनवरी। पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को तवी नदी के किनारे से फिर से जोड़ने की एक बड़ी पहल के तहत, पहला तवी बोटिंग फेस्टिवल बुधवार को जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित आर्टिफिशियल लेक में शुरू किया गया।

इस फेस्टिवल का उद्घाटन डिविजनल कमिश्नर जम्मू, रमेश कुमार और विधायक जम्मू ईस्ट, युधवीर सेठी ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू, डॉ. राकेश मिन्हास, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और CEO, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, डॉ. देवांश यादव और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मौजूदगी में किया।

यह दो दिवसीय फेस्टिवल, जो बुधवार और गुरुवार को हो रहा है,

जम्मू शहर के बीचों-बीच बोटिंग गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है।

यह कार्यक्रम शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक जनता के लिए मुफ्त है, जिससे निवासी नए विकसित रिवरफ्रंट का करीब से अनुभव कर सकें। उद्घाटन के दिन बड़ी संख्या में निवासी पहुंचे, और इस पहल को जम्मू के लिए एक ऐतिहासिक क्षण और स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मनोरंजक आकर्षण बताया। सभा को संबोधित करते हुए, विधायक जम्मू ईस्ट, युधवीर सेठी ने इस पहल को जम्मू के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, और कहा कि बोटिंग सुविधा एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगी और क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधि को काफी बढ़ावा देगी।

जम्मू-कश्मीर की गणतंत्र दिवस झांकी ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया

जम्मू, 28 जनवरी। जम्मू और कश्मीर की गणतंत्र दिवस झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और गर्व का क्षण है।

यह सम्मान जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक उत्कृष्टता और इसकी जीवंत परंपराओं को रेखांकित करता है, जिन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर प्रदर्शित किया गया।

जम्मू और कश्मीर की झांकी, जिसका विषय फ़एक जीवंत कैनवासफ़ था, ने एक दृश्यात्मक रूप से आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत की, जिसमें क्षेत्र की सदियों पुरानी कलाओं, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं का जश्न मनाया गया। झांकी ने शिल्प कौशल, प्रदर्शन और कहानी कहने का एक सहज मिश्रण पेश किया, जो केंद्र शासित प्रदेश की कालातीत रचनात्मक भावना को दर्शाता है।

झांकी में जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान के पर्याय माने जाने वाले प्रतिष्ठित हस्तशिल्पों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जिसमें पश्मीना बुनाई, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, कालीन बुनाई, पपीयर-माचे, तांबे के बर्तन और बसोहली लघु चित्रकला शामिल हैं - जिनमें से प्रत्येक परिष्कृत कौशल और कलात्मक महारत की पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है।

दृश्य कथा एक भव्य नक्काशीदार समोवर से शुरू हुई, जो कश्मीरी मेहमाननवाजी और गर्मजोशी का प्रतीक है, जो पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला और हाउसबोट की छवियों के माध्यम से बहती है, जो क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है। झांकी के केंद्र में, एक पारंपरिक गांव के थड़े पर मंचित डोगरा छज्जा प्रदर्शन ने सामुदायिक जीवन, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक निरंतरता को उजागर किया।

ताल, रंग और गति जोड़ने के लिए जीवंत लोक नृत्य प्रदर्शन शामिल थे, जिनमें रौफ, कुड, जगर्ना, पहाड़ी, गोजरी और दुम्हल शामिल थे, जो एक साथ जम्मू और कश्मीर के विविध जातीय और सांस्कृतिक ताने-बाने को दर्शाते थे। झांकी का समापन एक विलो टोकरी में व्यवस्थित रंगीन पपीयर-माचे कलाकृतियों के एक आकर्षक प्रदर्शन के साथ हुआ, जो प्रतीकात्मक रूप से जम्मू और कश्मीर को कला, परंपरा और रचनात्मकता के एक गतिशील, जीवंत कैनवास के रूप में प्रस्तुत करता है।

यह प्रशंसित उपस्थिति गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू और कश्मीर की झांकी की एक बड़ी वापसी का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय मंच पर केंद्र शासित प्रदेश की नवीनीकृत सांस्कृतिक उपस्थिति और अपनी समृद्ध अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

झांकी का विचार, डिजाइन और अवधारणा प्रसिद्ध कलाकार श्री बलवंत ठाकुर के नेतृत्व में किया गया था, जो पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता हैं। श्री ठाकुर ने आठ साल तक जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है और उनके पास कल्चरल लीडरशिप का बहुत ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ढ्ढष्टष्टक्र) के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है और दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का नेतृत्व किया है।

सोनमर्ग में हुई घटना के बाद गांदरबल पुलिस ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की

श्रीनगर, 28 जनवरी । कल रात लगभग 10:15 बजे सोनमर्ग के न्यू ट्रक यार्ड के पास हिमस्खलन हुआ। सौभाग्य से इसका प्रभाव न्यूनतम रहा और किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पुलिस टीम और एसडीआरएफ ने स्थिति का जायजा लेने के लिए समय पर संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई की।

संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं और क्षेत्र में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए गांदरबल पुलिस आम जनता पर्यटकों और परिवहनकर्ताओं से हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने या रुकने से सख्ती से बचने का आग्रह कर रही है।

हिमस्खलन की संभावना बहुत अधिक है और संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। लोगों से आग्रह है कि वे आधिकारिक सलाहों का पालन करें स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करें और सोनमर्ग मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

गांदरबल पुलिस जनता की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी से सतर्क रहने और जिम्मेदारी से व्यवहार करने का अनुरोध करती है।

यासीन मलिक को मृत्युदंड देने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन.आई.ए) की याचिका पर 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 28 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने बुधवार को मामले में सुनवाई की। बेंच ने एजेंसी की तरफ से किए गए अनुरोध को मंजूरी देते हुए कहा, अपीलकर्ता के वकील को चार हफ्ते का और समय दिया जाता है। कोर्ट ने अपील को आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।

एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मलिक को आतंकी फंडिंग के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है जिसके लिए मौत की सजा दी जाए। एजेंसी का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए मौत की सजा ही उचित है। नवंबर 2025 में पिछली सुनवाई के समय एनआईए ने अपील की सुनवाई के लिए इन-कैमरा कार्यवाही की मांग की थी। कोर्ट ने संकेत दिया था कि एजेंसी की ओर से औपचारिक रूप से याचिका दायर करने के बाद अनुरोध पर विचार किया जाएगा। एनआईए ने कार्यवाही के लिए एक प्राइवेट वर्चुअल सुनवाई लिंक की भी मांग की थी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए यासीन मलिक ने तब अपील के फैसले में लगभग तीन साल की लंबी देरी के कारण मानसिक परेशानी की शिकायत की थी। यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में कहा है कि 1990 के बाद से केंद्र में सत्ता में रही अलग-अलग 6 सरकारों ने कश्मीर की समस्याओं के हल के लिए उनसे बात की थी। बता दें कि पूरा मामला 2017 के टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें मलिक पर हवाला, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से फंडिंग और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप हैं। एनआईए ने दावा किया कि मलिक ने 1990 के दशक में कई हत्याओं और अपहरणों में भूमिका निभाई, जिसमें वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या भी शामिल है।

LG कविंदर ने एयर फ़ोर्स स्टेशन लेह में लगभग 452 करोड़ रुपये की पैरेलल टैक्सी ट्रैक परियोजना का उद्घाटन किया

लेह, 28 जनवरी। लद्दाख के उपराज्यपाल, श्री कविंदर गुप्ता ने आज एयर फ़ोर्स स्टेशन लेह में पैरेलल टैक्सी ट्रैक परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। PTT परियोजना, जिसे 2023 में शुरू किया गया था और खराब मौसम और सीमित कार्य मौसम के बावजूद लगभग 452 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है, मुख्य रनवे के रूप में काम करने की क्षमता रखती है, जिससे एयर कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, हवाई यातायात प्रवाह बढ़ेगा और हवाई यात्रा के माध्यम से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।उपराज्यपाल ने कहा कि लेह एयरफ़ील्ड उत्तरी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है और लद्दाख के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में भी कार्य करता है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह के माध्यम से सड़क संपर्क बंद रहता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक परियोजना में एक समानांतर टैक्सी ट्रैक, दो बड़े विमान फैलाव और पांच टैक्सी लिंक का निर्माण शामिल है, जो सभी भारी विमानों के संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह परियोजना सैन्य

और नागरिक उड्डयन दोनों के लिए एयरफ़ील्ड की परिचालन दक्षता, सुरक्षा और प्रतिक्रियाशीलता में काफी सुधार करेगी।उपराज्यपाल ने कहा कि नए टैक्सी ट्रैक पर सैन्य विमानों का संचालन कुछ प्रतिबंधों के साथ पहले ही शुरू हो चुका है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन नागरिक हवाई यातायात के लिए सुविधा को पूरी तरह से चालू करने के लिए ग्लोरी हिल के पास की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

मातृत्व का अहसास खूबसूरत

खुबसूरत अहसास है मातृत्व। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप मां बनने वाली हैं, उसी समय से गर्भस्थ शिशु के साथ एक रिश्ता बन जाता है। उसका विकास सही ढंग से हो, इसके लिए आप हर एहतियात बरतने की कोशिश करती हैं। इस लिहाज से खानपान पर ध्यान देना सबसे जरूरी हैं, क्योंकि आपके जरिए ही पोषण गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। अगर आपका खानपान ठीक नहीं है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप संतुलित आहार के सेवन की आदत डालें।

गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर भोजन के जरिए प्राप्त होने वाली ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चत करता है। इस दौरान आपको अपना खानपान ऐसा रखना चाहिए कि शरीर को कुछ विशेष विटामिन्स और मिनरल्स जैसे फोलिक एसिड और आयरन इत्यादि और कुछ अधिक कैलोरी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड से दूर रहें। यदि किसी महिला का खानपान पहले से ही संतुलित पोषण वाला रहा है तो उसके शरीर में इन तत्वों का कुछ भंडार रहता है, जिससे गर्भस्थ शिशु की जरूरत पूरी हो सके। ऐसे में मां की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

भोजन की मात्रा :

अक्सर लोग सलाह देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान मां को दो लोगों की जरूरत के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए, जबकि हकीकत में एक सामान्य महिला को गर्भावस्था के पहले छह माह तक अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती। इस दौरान भूख के अनुसार भोजन करना ही काफी रहता है।

जरूरत के मुताबिक आहार :

शरीर की बढ़ी हुई जरूरतों के अनुसार आपको संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार का पोषण प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व (कार्बोहाइड्रेट्स),शरीर का निर्माण करने वाले तत्व (प्रोटीन) और सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व (मिनरल्स-विटामिन्स) इत्यादि की उचित मात्रा वाला आहार संतुलित आहार कहलाता है। शरीर की अवस्था के अनुसार भोजन में इन पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था, शरीर की बनावट या शारीरिक मेहनत के अनुसार इस जरूरत का निर्धारण होता है।

ऊर्जा :

आमतौर पर गर्भावस्था के अंतिम महीनों में शरीर को कुछ अधिक मात्रा में कैलोरी की जरूरत होती है (हालांकि यह बढ़ोत्तरी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आहार विशेषज्ञ भोजन में रोजाना 300 कैलोरी अधिक शामिल करने की सलाह देते हैं। इस जरूरत को आप हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थो जैसे दूध, नट्स, सूखे मेवों, सोया उत्पादों के सेवन के जरिए पूरा कर सकती हैं।

प्रोटीन :

प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा गर्भस्थ शिशु के तेजी से विकास, गर्भनाल, स्तन ग्रंथियों व गर्भाशय के विस्तार, एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण व भंडारण, सहज प्रसव, मां के दूध के निमार्ण के लिए जरूरी है। मां के जरिए गर्भस्थ शिशु तक अमीनो एसिड पहुंचाने के लिए भी यह जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान रोजाना आहार में 15 ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा शामिल करने की सलाह दी जाती है। दूध, मांस, अंडा और चीज इत्यादि प्रोटीन के अच्छे स्त्रोत हैं।

आयरन :

गर्भावस्था के दौरान आहार में रोजाना आठ ग्राम आयरन की अतिरिक्त मात्रा यानी 38 ग्राम आयरन प्रतिदिन भोजन में शामिल करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर जन्म के समय शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 18-22 मिली. /डीएल (डेसीलीटर) रहता है। गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल के विकास के लिए आयरन बहुत जरूरी है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए भी इसकी समुचित मात्रा प्राप्त होना आवश्यक है। हरी सब्जियां, अंडा, दालों और आयरन युक्त नमक इसका अच्छा स्त्रोत हैं।

फोलिक एसिड :

एक सामान्य महिला को रोजाना 100 मिलीग्राम फोलिक एसिड की जरूरत होती है, पर विशेषज्ञ गर्भावस्था के दौरान रोजाना 400 मिलीग्राम फोलिक एसिड प्राप्त करने की सलाह देते हैं। इसकी कमी से गर्भावस्था में मैक्रोसाइटिक एनीमिया व गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क व रीढ़ के विकास में दोष उत्पन्न हो सकता है। गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक व सिट्रस फलों में यह अ%छी मात्रा में पाया जाता है।

कैल्शियम :

गर्भस्थ शिशु की हड्डियों व दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में इसकी करीब 25-30 ग्राम मात्रा गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। दूध, दही, मट्ठा इत्यादि इसके अच्छे स्त्रोत हैं। इनमें उच्च मात्रा में कैल्शियम के साथ ही विटामिन बी 12 भी पाया जाता है। अगर आपको दूध और उससे निर्मित उत्पादों से एलर्जी है तो इन तत्वों के सेवन के विषय में अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकती हैं।

विटामिन ए :

आमतौर पर एक महिला को 2400 माइक्रोग्राम बी कैरोटिन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान भी इसकी इतनी ही मात्रा ग्रहण करने की जरूरत होती है। अंडे की जर्दी, मक्खन, गहरे हरे और पीले रंग की सब्जियां और फल विटामिन ए के अच्छे स्त्रोत हैं।

विटामिन डी :

मां का शरीर कैल्शियम को भली प्रकार एब्जार्ब्व कर सके, इसके लिए विटामिन डी लेना बेहद जरूरी है। सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, जिसकी मदद से शरीर दूध, दालों इत्यादि से मिलने वाले कैल्शियम को भली प्रकार ग्रहण कर पाता है।

सोडियम :

किसी प्रकार के विकारों, डिसऑर्डर और कमी से बचने के लिए एक सामान्य महिला के शरीर में सोडियम की समुचित मात्रा पहुंचनी चाहिए। आहार में इसकी कमी से हार्मोन संबंधी बदलाव उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऐसी दवाओं से बचना चाहिए, जिनसे बार बार-बार टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि इससे शरीर से जरूरी सोडियम भी निकल जाता है। अगर हाइपरटेंशन जैसी कोई समस्या है, तब सोडियम की मात्रा सीमित करने की सलाह दी जाती है।

तरल पदार्थ :

शरीर में पानी की कमी न होने दें। भरपूर मात्रा में पानी पीने के साथ ही ताजे फलों का रस ग्रहण करें। जब भी घर से बाहर जाएं तो पीने का पानी साथ ले जाएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अशुद्ध पानी के कारण होती हैं।

वसा :

इस दौरान अपने कुकिंग ऑयल व वसा पर ध्यान देना भी जरूरी है। घी, मक्खन और नारियल तेल में सैचुरेटेड फैट्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए इनके सेवन से बचना चाहिए। इनके अलावा वनस्पति घी में ट्रांस फैट्स की मात्रा अधिक होती है और यह भी सैचुरेटेड फैट के जितना ही नुकसानदेह होता है।

सेहत पर न पड़े सर्दी का प्रकोप

इन दिनों उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। आमतौर पर सेहत के लिए अच्छा माना जाने वाला मौजूदा मौसम असावधानियां बरतने पर कई रोगों का कारण भी बन सकता है, लेकिन कुछ सजगताएं बरतने पर इस मौसम में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। अगर दुर्भाग्यवश कुछ रोगों से ग्रस्त हो भी गए, तो उनका इलाज मौजूद है, लेकिन याद रखें, इलाज से बेहतर बचाव है..

प्रोस्टेट ग्रंथि का सामान्य आकार से बढ़ना या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया (बीपीएच) के मामले अन्य ऋतुओं की तुलना में सर्दियों में कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि सर्दी का मौसम सिम्पैथेटिक न?र्वस को उत्तेजित करता है। यह स्थिति प्रोस्टेट की मांसपेशियों में संकुचन को बढ़ा सकती है। इस कारण सर्दियों में बीपीएच की समस्या से संबंधित कुछ ज्यादा ही मामले सामने आते हैं।

लक्षण

- पतली धार में पेशाब होना।
- पेशाब करने के लिए अधिक जोर लगाना और बार-बार पेशाब करना।
- पेशाब के प्रवाह में बाधा।
- पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि पूरा पेशाब नहीं निकला है।
- पेशाब को रोके रखने में असमर्थता।
- पे

शा

ब में जलन और पेशाब के दौरान रक्त निकलना।

यदि किसी व्यक्ति में उपर्युक्त लक्षणों में से दो से अधिक लक्षण मौजूद हैं, तो उसे शीघ्र ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

जांचें

डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट स्पेशिफिक एंटीजन (पीएसए) रक्त परीक्षण, गुदा का अल्ट्रासाउंड, पेशाब के प्रवाह की जांच और सिस्टोस्कोपी जांचों से इस रोग का पता चलता है।

उपचार

प्रोस्टेट का उपचार दवाओं या सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि काफी रोगियों पर दवा काम नहीं कर सकती है। इसलिए सर्जरी अधिक बेहतर और कारगर प्रक्रिया साबित होती है।

टीयूआरपी (ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट): आज भी यह सर्जरी सबसे अधिक स्वीकार्य है। यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध सर्जिकल प्रक्रिया है, लेकिन इस सर्जरी के बाद रोगी को कुछ असहजताएं भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। जैसे रोगी को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, कैथेराइजेशन का समय लंबा होता है, रिकवरी में अधिक समय लगता है और उसे रक्तस्राव और 'टीयूआरपी सिंड्रोम' नामक समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

नवीनतम उपचार

एचओएलईपी (होलमियम लेजर इनुक्लीएशन ऑफ प्रोस्टेट): यह बढ़ी हुई प्रॉस्टेट ग्रंथि के इलाज की नवीनतम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक होलमियम लेजर मशीन से जुड़े 550 माइक्रॉन लेजर फाइबर के इस्तेमाल से प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़े हुए 'लोब्स' या भाग को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाली हुई ग्रंथि को उसके बाद मूत्राशय (यूरीनरी ब्लैडर) में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक मॉर्सीलेटर (एक मशीन) को दूरबीन के माध्यम से डाला जाता है, जो ग्रंथि को खींच लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में 45 से 90 मिनट का समय लगता है, जो ग्रंथि के आकार पर निर्भर करती है। पूरी प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से रक्त की कोई हानि नहीं होती है और रोगी 24 से 36 घंटे के अंदर घर वापस चला जाता है।

ऑफिस में कैसे रहें सेहतमंद

स्वस्थ एवं फिट रहने के लिए व्यस्त रहना बहुत ही जरूरी हैं अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर आप आसानी से व्यस्त भी रह सकेंगे और काम भी समय से पूरा कर सकेंगे। कैसे, आइए जानें।

ऑफिस में बैठने का काम हो तो बीच-बीच में टहलें। अपनी फाइलें, रजिस्टर आदि स्वयं ही उठाकर कर रखें या फिर लंच टाइम में अपने केबिन में ही टहल लें। किसी भी तरीके से 15-20 मिनट तो अवश्य ही चलें ताकि शरीर की कसरत हो जाए।

- घर पर ही ऐसा नाश्ता तैयार करके रख लें, जो सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी हो। उसे पैक करके ऑफिस ले
- आएँ। आटे की नमकीन-मीठी मट्ठियाँ, भुना चिवड़ा, काले भुने चने आदि पदार्थ ज्यादा लेने की कोशिश करें।
- आप ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो जब भी रेस्टोरेंट में लंच करना पड़ जाए तो सलाद, सूप आदि अधिक लें।
- तले-भुने व गरिष्ठ भोजन की बजाए ऐसे भोजन का आर्डर दें,जो आपके लिए नुकसानदेह न हो।
- गर्मी के मौसम में ठंड पेय लेते समय ध्यान रखें कि ये कैमिकल युक्त न हों। आप जूस, शरबत, शिकंजी अधिक मात्रा में ले सकते हैं।
- काम करते-करते थक जाएँ तो कुर्सी पर ही विश्रामदायक मुद्रा में बैठ जाएँ। आँख बंद कर लें। ऐसा 10 मिनट तक करें।

पानी पिएँ, खूब जिएँ

एक सामान्य व्यक्ति को पूरे दिन में औसतन 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में पानी की उचित मात्रा बनी रहती है। कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है।

पानी भरपूर पीने से गुर्दे भी ठीक से काम करते हैं यानी गुर्दे ठीक काम करें, इसके लिए पानी भरपूर पीना बहुत जरूरी है। इससे मूत्र भी ज्यादा आता है और मूत्र के द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं।

आपके मूत्र का रंग पीला है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है। यदि आप बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल लेते हैं और पानी भी भरपूर पीते हैं, ऐसे में आपके मूत्र का रंग पीला हो तो चिंता न करें। बी कॉम्प्लेक्स लेते समय ऐसा होता है।

आप कोई अन्य दवा का सेवन कर रहे हों तो भी मूत्र का रंग बदल जाता है, इसमें चिंता न करें। शरीर में गरमी बढ़ जाने पर भी मूत्र पीला आ सकता है, बस पानी भरपूर पिएँ। शरीर में लगातार मेटाबोलिक क्रियाएँ चलती रहती हैं, जिसके लिए पानी की लगातार जरूरत होती है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जीडीसी महानपुर में एक सप्ताहीय एनएसएस विंटर कैंप का शुभारंभ

कठुआ, 28 जनवरी (हि.स.)। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महानपुर की एनएसएस इकाई द्वारा 28 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे एक सप्ताहीय एनएसएस विंटर कैंप का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन कॉलेज की प्राचार्य प्रो. (डॉ.) संगीता सूदन के मार्गदर्शन में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रुपाली जसरोटिया द्वारा किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर डॉ. रुपाली जसरोटिया ने स्वागत भाषण देते हुए शिविर के उद्देश्यों एवं गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रो. (डॉ.) संगीता सूदन ने एनएसएस स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए उन्हें ‘नॉट मी, बट यू’ के मूल मंत्र के अनुरूप समाज सेवा, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान दूसरे सेमेस्टर के एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा देशभक्ति समूह गीत प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

शिविर के सफल संचालन हेतु प्रतिभागियों को छह समूहों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक समूह के लिए एक प्रमुख एवं उप-प्रमुख नियुक्त किए गए। इस अवसर पर कॉलेज के सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी उपस्थित रहे।

4 से 6 फरवरी तक होंगे 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.)। 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए जम्मू-कश्मीर टीम के चयन ट्रायल 4 से 6 फरवरी 2026 तक सुभाष स्टेडियम, उधमपुर में आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शुरू होंगे। जम्मू-कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव डॉ. कुलदीप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रायल्स के माध्यम से राज्य की पुरुष कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा, जो 24 से 27 फरवरी 2026 तक गुजरात के वडोदरा स्थित इंडोर कॉम्प्लेक्स में होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेगी।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि पुरुष वर्ग के लिए पात्रता मानदंड के तहत खिलाड़ियों का वजन 85 किलोग्राम या उससे कम होना चाहिए, जबकि आयु को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी संबद्ध जिलों और क्लबों से आग्रह किया कि वे अपने पंजीकृत खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए भेजें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार या केंद्रीय बलों में कार्यरत खिलाड़ी अपने संबंधित विभाग से अनुमति पत्र परमिशन लेकर आएं। केवल वही खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग लेने के पात्र होंगे जो जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की दो फोटो कॉपी, माता-पिता से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विभागीय अनुमति पत्र, डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तथा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का पंजीकरण कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।

कठुआ के विकास को नई गति, विधायक डॉ. भारत भूषण ने तीन विकास कार्यों का किया उद्घाटन

कठुआ, 28 जनवरी (हि.स.)। कठुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए बुधवार को विधायक डॉ. भारत भूषण ने कठुआ के वार्ड नंबर 6 और 7 में तीन गलियों एवं नालियों का विधिवत उद्घाटन किया। इन सभी विकास कार्यों पर कुल 18.50 लाख रुपये की लागत आई है।

उद्घाटित कार्यों में वार्ड नंबर 7 में दो गली-नाली परियोजनाएं जबकि वार्ड नंबर 6 में एक गली-नाली परियोजना शामिल है।

इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार होने की उम्मीद है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण ने कहा कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कठुआ के समग्र विकास के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अनिरुद्ध शर्मा, हरबंस लाल, डॉ. शिव कुमार, स्मृति विद्या देवी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष देविंदर सिंह सन्नी, रमेश शर्मा, सरदार हरबिंदर सिंह, कविता, बेबी रानी, अमित सूदन, भानु प्रताप सिंह, दीपक कुमार सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विधायक ने वार्ड के निवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और उन्हें शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

बारामूला के उपायुक्त ने संपूर्णता 2.0 की तैयारियों पर बैठक की अध्यक्षता की

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.) बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज डीसी कार्यालय के मुख्य बैठक कक्ष में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की व्यापकता सुनिश्चित करने और तैयारियों का आकलन करना था।

बैठक के दौरान डीसी ने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और पशुधन टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतकों पर क्षेत्रवार प्रदर्शन की समीक्षा की।

इस बैठक में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों की कार्यक्षमता आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण कवरेज, आंगनवाड़ी केंद्रों की परिचालन दक्षता, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और मवेशियों के टीकाकरण जैसे संकेतकों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

डीसी ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अभियान अवधि के दौरान एडीपी के तहत 5 और एबीपी के तहत 6 प्रमुख संकेतक को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभियान का जमीनी स्तर पर ठोस सुधार होना चाहिए।

मिंगा शेरपा ने विशेष रूप से विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक संकेतक को पूरी तरह से कवर करने के उद्देश्य से तीन महीने की अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत, समयबद्ध कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

जंग लगा मोर्टार का गोला किया गया नष्ट

पुंछ, 28 जनवरी (हि.स.)। बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास एक गांव से जंग लगा मोर्टार का गोला बरामद किया गया और नियंत्रित विस्फोट में उसे निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान से आया यह मोर्टार का गोला पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गांव में गिरा था। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने गोले को देखा और स्थानीय सेना इकाई और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर भेजा गया और मोर्टार को नष्ट कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर के जिले वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पहलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.)। जम्मू, पुलवामा और बारामूला जिले जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में उभरे हैं जो वित्तीय पहुंच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन योजनाओं के कवरेज में उल्लेखनीय सुधार और वर्ष-दर-वर्ष प्रगति के लिए जिला प्रशासनों के प्रयासों की सराहना की है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों को दुर्घटना और जीवन बीमा कवर के साथ-साथ पेंशन लाभ भी प्रदान करती हैं।

पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज सोना चोरी का मामला सुलझा

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.)। जम्मू जिले के पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में 20 सितंबर 2025 को एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि शॉपिंग के दौरान शिकायतकर्ता का सोना चोरी हो गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जम्मू सिटी नॉर्थ विवेक शेखर ने स्वयं मामले की निगरानी की और अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने जांच के दौरान सोना चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी किया गया सोना भी बरामद कर लिया गया।

इस पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी नॉर्थ विवेक शेखर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जम्मू पुलिस आम जनता की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कठुआ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, खैर की अवैध तस्करी नाकाम

कठुआ, 28 जनवरी (हि.स.)। अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ वन विभाग की टीम ने खैर लकड़ी की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है।

जानकारी के अनुसार वन विभाग की बुधि ब्लॉक टीम ने गांव रौड़ी सहर पंचायत के पास नाका लगाकर एक टाटा योद्धा लोड कैरियर नंबर जेके08एल-1637 को जांच के लिए रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें खैर की 15 सिल्लियां अवैध रूप से ले जाई जा रही पाई गईं। यह कार्रवाई बुधि ब्लॉक के ब्लॉक अधिकारी द्वारा फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर की गई। वाहन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(1) व 52(2) के तहत जब्त किया गया। साथ ही धारा 41, 41-I, 42 तथा एसआरओ-111/2016 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जब्ती की कार्रवाई रेंज अधिकारी कठुआ नितिन खजूरिया की निगरानी में तथा प्रभागीय वन अधिकारी कठुआ अंकित सिन्हा (आईएफएस) के समग्र मार्गदर्शन में की गई। जब्त वाहन और अवैध वन उपज को वन परिसर कठुआ में सुरक्षित रखा गया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वन विभाग ने इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वन सुरक्षा बल के सहयोग की सराहना की है। विभाग का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों के आपसी तालमेल से जिले में खैर और अन्य वन उपज की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। वन विभाग कठुआ ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कटाई, तस्करी या वन उपज के गैरकानूनी परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि वन संपदा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अवैध खनन में लिप्त 4 डंपर जब्त

कठुआ, 28 जनवरी (हि.स.)। अवैध खनन के खिलाफ जारी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने आउट पोस्ट घड़ी थाना कठुआ के अधिकार क्षेत्र उज्ज नदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार डंपरों को जब्त किया है।

यह कार्रवाई एसडीपीओ कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस के अनुसार ये डंपर बिना किसी वैध अनुमति और ई-फॉर्म के निर्माण सामग्री के अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त पाए गए। जानकारी के अनुसार पीएसआई रजत कोतवाल प्रभारी आउट पोस्ट घाट्टी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान चार डंपरों को अवैध खनन/परिवहन में लिप्त पाए जाने पर जब्त किया। जब्त किए गए सभी वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग कठुआ को सौंप दिया गया है।

पत्नी ने ही की थी पति की हत्या, कठुआ पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस

कठुआ/बिलावर, 28 जनवरी (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने एक ब्लाइंड हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार बिलावर थाना क्षेत्र के धार दुगनू गांव निवासी बिट्टू राम का शव 9 अक्टूबर 2025 को नाले में संदिग्ध हालत में मिला था। जांच के दौरान शरीर पर चोटों और गले पर निशान मिलने से हत्या की आशंका गहराई। वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के बाद मामले को हत्या में तब्दील कर एफआईआर दर्ज की गई।

पूछताछ में मृतक की पत्नी सिमरो देवी ने अवैध संबंधों के चलते हुए विवाद के बाद पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने मामले से जुड़ी अहम बरामदगियां भी की हैं।

डोडा पुलिस ने अवैध शराब की 61 बोतलें जब्त कीं;आरोपी गिरफ्तार

डोडा, 28 जनवरी (हि.स.)। डोडा पुलिस ने अवैध शराब की 61 बोतलें जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया।

आज पीएसआई अंकुश भारती द्वारा थथरी पुलिस स्टेशन में एक लिखित मामला दर्ज किया गया। यह मामला एनएचडब्ल्यू-244 पर कामसू स्थित जीरो मोड़ पर किए गए यातायात जांच अभियान से संबंधित था।

जांच के दौरान डोडा से थथरी की ओर आ रही बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। उसने रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया हालांकि नाका पार्टी ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर अवैध शराब से भरे दो बैग बरामद हुए जिनमें जेके स्पेशल व्हिस्की की 3 बोतलें 18 क्वार्टर और 40 क्वार्टर शामिल थीं। कुल बरामद अवैध शराब की मात्रा 61 बोतलें क्वार्टर थी। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान विमल कुमार पुत्र कुलदीप सिंह निवासी नंदना तहसील कामसू के रूप में हुई। वह मौके पर शराब रखने का कोई वैध परमिट या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रारंभिक जांच से पता चला कि शराब अवैध रूप से खरीदी गई थी और बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी। थथरी पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम की धारा 48 के तहत एफआईआर संख्या 10 2026 दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना पर गहरा शोक किया व्यक्त

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर ने आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और विमान में सवार अन्य लोगों के असामयिक निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और राजनीतिक जगत एवं नागरिक स्तब्ध हैं।

जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा (सीए) ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार जी एक समर्पित लोक सेवक थे जिनके अनुभव और नेतृत्व ने महाराष्ट्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने इस क्षति को अपूरणीय बताया और दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा, जम्मू में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली रैदासिया समाज की यात्रा

जम्मू, 28 जनवरी (हि.स.)। सत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुरु रविदास सभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सभा के मुख्य कार्यालय कृष्णा नगर, जम्मू से आरसी भसीन की संयोजकता में निकाली गई। शोभा यात्रा को बिरादरी के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सदस्यों—सीएल बनाल, अमर नाथ बावौरिया, परस राम अग्राल, एमआर बंगोत्रा, इंजीनियर बीआर खडगल, इंजीनियर डी डी गोरखा, डॉ. राजिंदर संध्याल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में रैदासिया समाज के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरि जी महाराज भी शोभा यात्रा में शामिल हुए।

शोभा यात्रा जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाहु फोर्ट गुरुद्वारा में संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में बिरादरी के लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन दर्शन को दर्शाती आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा जगह-जगह स्टॉल लगाकर जलपान, पानी और प्रसाद वितरित किया गया।

बाहु फोर्ट पहुंचने पर श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरि जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रवचन दिया।

इसके उपरांत गुरु रविदास सभा बाहु फोर्ट की ओर से विभिन्न सभाओं के पदाधिकारियों और बिरादरी के प्रमुख सदस्यों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला जम्मू के सिविल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। आयोजन समिति ने सिविल व पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही कार्यक्रम की कवरेज करने वाले समस्त मीडिया संस्थानों का भी धन्यवाद किया।

कक्षा 11वीं का परिणाम फरवरी के पहले सप्ताह तक घोषित होने की संभावना-जेकेबीओएसई

श्रीनगर, 28 जनवरी (हि.स.) जेकेबीओएसई के एक अधिकारी ने बताया कि कक्षा 11वीं की परीक्षा के परिणाम फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। मीडिया से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) के अध्यक्ष गुलाम हसन शेख ने कहा कि कक्षा 11वीं के परिणाम संकलन की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि हम 2 फरवरी 2026 तक परिणाम घोषित कर देंगे। लगभग 81622 छात्रों ने - कश्मीर से 654001 और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों से 17621 - कक्षा 11वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। जेकेबीओएसई के अध्यक्ष ने कहा, यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम फरवरी के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित कर देंगे।

जीडीसी हीरानगर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

कठुआ/हीरानगर, 28 जनवरी (हि.स.)। जीएलडीएम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर में मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक दिवसीय संवेदनशीलता एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य प्रो. (डॉ.) प्रज्ञा खजूरिया ने की जिन्होंने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक और सामाजिक दबावों पर प्रकाश डालते हुए मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला की मुख्य वक्ता राजकीय अस्पताल हीरानगर की मेडिकल ऑफिसर डॉ. नेहा शर्मा रहीं जिन्होंने तनाव प्रबंधन, आत्म-देखभाल और भावनात्मक जागरूकता पर उपयोगी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में शिक्षकों ने परामर्श सेवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ यह कार्यशाला अत्यंत लाभकारी रही।

संपादकीय

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मुद्दे का राजनीतिकरण न करें

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का भविष्य—जिसकी मान्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने न्यूनतम मानकों में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए कथित तौर पर रद्द कर दी—जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए।

इस 'प्रतिष्ठित' संस्थान में प्रवेश मानदंडों को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध और प्रदर्शन किए गए थे। इस पूरे प्रकरण के राजनीतिकरण का जो परिणाम सामने आया, उसे देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के मुद्दे पर कोई आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया न दी जाए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर SMVDIME जैसी एक और असफलता वहन नहीं कर सकता।

जैसे-जैसे कई संगठन कश्मीर घाटी में NL की स्थापना के प्रस्ताव के विरोध में सामने आ रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय जम्मू में स्थापित किया जाए, दोनों क्षेत्रों के बीच टकराव की आशंका बढ़ती दिख रही है।

इसी क्रम में जम्मू विश्वविद्यालय के कुछ विधि छात्रों को थोड़े समय के लिए हिरासत में लिया गया, जब उन्होंने जम्मू में NLU की मांग को लेकर तवी पुल को अवरुद्ध कर दिया।

हालांकि उन्हें जम्मू क्षेत्र के लिए NLU की मांग करने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इससे शहर का सामान्य जीवन बाधित नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि छात्र किसी राजनीतिक संगठन के हाथों अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल न हो रहे हों। बेहतर होता कि सड़कें जाम करने के बजाय छात्र नेताओं ने पहले जम्मू क्षेत्र के मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी होती, क्योंकि अंततः किसी भी मुद्दे या संकट के समाधान का एकमात्र रास्ता संवाद ही है। इस मामले में संवाद का अभाव स्पष्ट दिखता है, क्योंकि बिना किसी बातचीत के छात्र चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित हो गए।

जब जम्मू-कश्मीर की सरकार स्वयं समय-समय पर सर्वांगीण विकास की बात करती है, तो जम्मू क्षेत्र के छात्र इसी आधार पर अपने क्षेत्र में NLU की मांग रख सकते हैं। जम्मू प्रांत के कई इलाके—जैसे पूंछ, डोडा, उधमपुर, सांबा आदि—अब भी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से वंचित हैं। इसलिए, सड़कों पर उतरकर हरु की मांग करने वाले संगठनों को चाहिए कि वे अपनी मांग के समर्थन में ठोस तर्क और आंकड़ों के साथ तैयारी करें और शासन में बैठे स्थानीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखें। उनकी मांग निस्संदेह वास्तविक है और इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।

यह भी संभव है कि सही माध्यम और सही तरीके से सरकार को विश्वास में लेकर जम्मू-कश्मीर में दो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं—एक जम्मू के लिए और दूसरा घाटी के लिए। अंततः, सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करना मांग उठाने का अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है कि इस मुद्दे को व्यावहारिकता और सही दृष्टिकोण के साथ सुलझाया जाए।

प्रगति @50 शासन को इरादा नहीं,डिलिवरी परिभाषित करती है

प्रगतिनिर्णय लेने, समन्वय करने और लागू करने के तरीके को नए तरीके से डिजाइन कर लगातार बनी रहने वाली इन संरचनात्मक कमियों को दूर करता है। प्रणालीगत समन्वयक के रूप में काम करते हुएयह मंत्रालयों, राज्यों और जिलों के निर्णयकर्ताओं को एक ही संस्थागत और डिजिटल मंच पर लाता है। यह फ़ाइलों के आदान-प्रदान, क्षेत्राधिकार की अस्पष्टता और विभागीय पत्राचार के कारण होने वाली देरी को समाप्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यान्वयन का विस्तृत दृष्टिकोण बहाल करता है, जिससे नेतृत्व फ़ाइलों की लंबित स्थिति के बजाय प्रणाली से संबंधित रुकावटों की पहचान कर सकता है।

– टी.के. रामचंद्रन

सरकार के दो परिवर्तनकारी कदमों—पीएम गति शक्ति और प्रगति—काविशाल परियोजनाओं की योजनाबनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने पर गहरा असर पड़ा है। इस लेख में हम बाद वाले कदम के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंसएंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्रारूप के तहत आयोजित 50वीं उच्च-स्तरीय समीक्षा दर्शाती है कि शासन के प्रति भारत सरकारके रुख और उसे संचालित करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह बदलाव नीयत से डिलिवरी की ओर, प्रक्रियागत अनुपालन से परिणामों की ओर तथा बिखरी हुई सत्ता से समन्वित एवं समयबद्ध कार्यान्वयन की ओर संकेतकरता है।इस प्रकार प्रगति केवल एक प्रशासनिक नवाचार भर नहीं है; बल्कि यह शासन की संरचना कीसोच-विचार कर की गई पुनर्रचना का प्रतिनिधित्व करता है।ऐसे में सवालयह उठता है कि जब शासन के अन्य मॉडल विफल रहे, तब यह मॉडल परिणाम देने में कैसे सफल हुआ?

प्रगति की आवश्याकता

सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी होना लगभग आम बात रही है। फिर भी, शायद ही कभी इस देरी कारण नीति में स्पष्ट जानकारी या वित्तीय मंजूरीका अभाव रहा। शासन प्रणालियों का बिखराव इस देरी का कारण रहा है। मंत्रालय ऊपरी से निचले स्तर तक या वर्टिकली कार्य करते हैं; राज्य और केंद्र क्रमिक रूप से काम करते हैं; और विवाद निपटाने के अधिकार-संपन्न मंच न होने के कारण, विवाद लंबित पड़ेरहते हैं। गतिविधियाँ बढ़ने के बावजूद जवाबदेही कमज़ोर होती जाती है। मुख्य समस्या कमज़ोर तालमेल और साइलो-बेस्ड समीक्षा तंत्र रहीहैं।

इसके परिणामस्वरूप, परियोजना की डिलिवरी का व्यापक उद्देश्य अक्सर कहीं खो जाता है। कई परियोजनाएँ जमीनी विवाद, पर्यावरण या वन मंजूरी, नियामक अनुमोदन, संविदा से जुड़े विवादोंया राज्यों के बीच तालमेल संबंधी चुनौतियों के कारण वर्षों तक अटकी रहीं। एक बहु-मंत्रालयीय और बहु-राज्यीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में, जहाँ प्रत्येक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाए हुए होती है, किसी के लिए भी दूसरे को राजी करना कठिन हो जाता है।

जब परियोजना की पूर्ति में कई राज्यों और मंत्रालयों को योगदान देना होता है, तोबैठकें करने, चर्चा करने, फील्ड दौरे करने, समितियाँ बनाने और अंतहीन पत्राचार करने की पुरानी प्रक्रिया बेअसर साबित होती है। यह एक ऐसा तरीका था, जिसमें चर्चा को निर्णय, गतिविधि को काम, गति को प्रगति और केवल नीयत को उपलब्धि समझ लिया जाता था।

प्रगति का आगमन

प्रगतिनिर्णय लेने, समन्वय करने और लागू करने के तरीके को नए तरीके से डिजाइन कर लगातार बनी रहने वाली इन संरचनात्मक कमियों को दूर करता है। प्रणालीगत समन्वयक के रूप में काम करते हुएयह मंत्रालयों, राज्यों और जिलों के निर्णयकर्ताओं को एक ही संस्थागत और डिजिटल मंच पर लाता है। यह फ़ाइलों के आदान-प्रदान, क्षेत्राधिकार की अस्पष्टता और विभागीय पत्राचार के कारण होने वाली देरी को समाप्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यान्वयन का विस्तृत दृष्टिकोण बहाल करता है, जिससे नेतृत्व फ़ाइलों की लंबित स्थिति के बजाय प्रणाली से संबंधित रुकावटों की पहचान कर सकता है।

प्रगतिके तहत होने वाली समीक्षा की अध्यक्षता करने में माननीय प्रधानमंत्री की भूमिका इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। उनका सीधा जुड़ाव इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि डिलिवरी राष्ट्रीय प्राथमिकता है और कार्यान्वयन की विफलताओं पर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। यह निर्णायक कार्रवाई को सुगम बनाता है और समीक्षा को परिणामों के लिए एक बाध्यकारी ढांचे में बदल देता है। इन समीक्षाओं के दौरान लिए गए निर्णय अंतिम, समयबद्ध और डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे जवाबदेही स्पष्ट और लागू करने योग्य होती है।

प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करती है। रीयल-टाइम डेटा, जियो-स्पैशियल विज़ुअलाइज़ेशन और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ सीधे संवाद हितधारकों के बीच जानकारी की असमानता समाप्त करते हैं और निर्णयों को साक्ष्यों के आधार पर लिया जाना सुनिश्चित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी प्रशासनिक निर्णय क्षमता को बदलने के बजाय उसे सुदृढ़ करती है, जिससे प्रणाली के भीतर नेतृत्व की जिम्मेदारी और मजबूत होती है।

प्रगतिमें समापन पर जोर दिया जाता हैऔर यही बात उसे पहले के समीक्षा तंत्रों से अलग बनाती है। समस्याएँ तब तक सक्रिय रहती हैं, जब तक उन्हें हल नहीं किया जाता, और उन्हें लगातार कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ट्रैक किया जाता है। केवल स्पष्टीकरण देना अब परिणामों का विकल्प नहीं है। समय के साथ, इस अनुशासन ने प्रशासनिक व्यवहार को बदल दिया है, जिससे मंत्रालयों और राज्यों को समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें बढ़ने से पहले हल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है

परिणाम

परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और आकलन करने योग्य हैं। 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में तेज़ गति से काम हुआ गई है। हाल के वर्षों में, प्रगतिके तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की दस परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिससे अड़चनों का जल्द समाधान हुआ और तेज़ी सेकार्यान्वयन संभव हुआ। मैं उदाहरण के रूप में दो परियोजनाओं को प्रस्तुत करूँगा।

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) एक विशाल परियोजना है, जिसमें केंद्र सरकार के संस्कृति, रक्षा, विदेश, रेल और राजमार्ग जैसे कई मंत्रालयों के साथ-साथ गुजरात सरकार भी शामिल हैं। साथ ही, कई तटीय राज्यों के पवेलियन स्थापित किए जाने हैं, इसलिए संबंधित राज्य भी इस परियोजना का हिस्सा हैं। पिछले वर्ष एनएमएचसीपरियोजना को प्रगतिके एजेंडे में शामिल करने से कई स्तरों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। सामान्यतः एजेंडे को प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा से कुछ महीने पहले सूचित किया जाता है, जिससे विभिन्न हितधारकों को प्राथमिकता के साथ मुद्दों को हल करने का अवसर मिलता है। परिणामस्वरूप, ज्यादातर मुद्दे जो आधिकारिक/मंत्रालय स्तर पर हल किए जा सकते हैं, पहले ही सुलझ जाते हैं और केवल मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता वालेशेष जटिल मुद्दे ही वास्तविक समीक्षा के दौरान उठाए जाते हैं।

इसी तरह, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू)-1 पर लागू की जा रही जल मार्ग विकास परियोजनाकी प्रगति के तहत दो बार समीक्षा की गई। यह परियोजना अब समापन चरण में है और अधिकांश लंबित मुद्दे हल हो चुके हैं।

प्रगति फोरम एक महत्वपूर्ण सत्य पर जोर देता है- सार्वजनिक मूल्य या पब्लिक वेल्यू केवल योजनाओं की घोषणा करने से नहीं, बल्कि मंजूर किए गए निवेश के नतीजों में परिणत होने से उत्पन्न होता है। अटकी हुई परियोजनाएँ केवल नीतियों को दोबारा निरुपित किए जाने के कारण ही आगे नहीं बढ़ी, बल्कि कार्यान्वयन के मार्ग को आसान बनाने और जवाबदेही लागू करने के कारण आगे बढ़ीं। प्रगतिका सहकारी संघवाद में योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों को एक ही रीयल-टाइम प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जानाबंटी हुई जिम्मेदारी के स्थान पर परिणामों की साझा जिम्मेदारी स्थापित करता है।

प्रगति @50 इस बात का सबूत है कि शासन के नतीजे संस्था की संरचना पर निर्भर करते हैं। साइलो समाप्त करके, कार्यान्वयन का व्यापक दृष्टिकोण बहाल करके और कार्य समाप्त करने को प्राथमिकता देकर, प्रगति यह दर्शाता है कि असरदार शासन का आशय केवल कार्यभार बढ़ाना नहीं,बल्कि पहले से स्वीकृत कार्य को तेज़ी, गुणवत्ता और तालमेल के साथ पूराकरना है।समयबद्ध कार्यान्वयन सेवाओं तक त्वरित पहुँच कायम करता है, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, क्षेत्रीय असमानताओं को घटाता है और सरकार की शासन करने की क्षमता में जनता का विश्वास मजबूत करता है।

प्रगति केवल नेतृत्व-प्रधान डिलिवरी का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि जटिल शासन को संचालित करने की रूपरेखा भी है। वैश्विक स्तर पर इसे मिल रही तवज्जो और प्रशंसा इसी बात का प्रमाण है।

(लेखक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं)

बजट 2026- ग्रीन एनर्जी को मिल सकती है नई उड़ान

– विवेक शुक्ला

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश तेजी से विकास कर रहा है और पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। ग्रीन एनर्जी यानी साफ और नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रोजन, भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2030 तक 500 गीगावॉट नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करने और साल 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

इस बजट से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र को कई उम्मीदें हैं, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मजबूत बनाएंगी।

सबसे पहले, ग्रीन एनर्जी क्षेत्र को उम्मीद है कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में सोलर पैनल, विंड टरबाइन और बैटरी स्टोरेज जैसी चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं आ सकती हैं। अभी भारत इनमें से कई सामान आयात करता है, जो महंगा पड़ता है। भारत में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट और येमनोको लिमिटेड के प्रमुख शैलेन्द्र बेबोरठा ने बीते दिनों राजधानी में हुई इंटरनेशनल कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि बजट में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती आयकर दर फिर से शुरू की जा सकती है। इससे लोकल उत्पादन बढ़ेगा और नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही, टेक्नोलॉजी और उपकरण विकास पर फोकस होगा, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। उदाहरण के लिए, सोलर मॉड्यूल और सेल बनाने वाली फैक्टरियों को सब्सिडी या टैक्स छूट मिल सकती है। इससे ग्रीन एनर्जी सस्ती हो जाएगी और आम लोग इसे अपनाएंगे।

दूसरी बड़ी उम्मीद स्टोरेज टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। सोलर और विंड एनर्जी दिन-रात उपलब्ध नहीं रहती इसलिए बैटरी स्टोरेज बहुत जरूरी है। बजट में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और बैटरी सिस्टम के लिए ज्यादा फंडिंग की उम्मीद है। देश के ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़े सब लोगों की चाहत है कि सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च करे, जैसे टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर्स और यूनिवर्सिटी-इंडस्ट्री सहयोग। इससे नई तकनीकें विकसित होंगी और एनर्जी स्टोरेज सस्ता होगा। साथ ही, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हाई-कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स और सब स्टेशनों पर निवेश बढ़ सकता है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में जोड़ना पड़ता है, वरना बिजली बर्बाद हो जाती है।

ग्रीन हाइड्रोजन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्रीन हाइड्रोजन साफ पानी और रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है और यह ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और पावर सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है। शैलेन्द्र बेबोरठा मानते हैं कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहा है, लेकिन इसे तेज करने के लिए बजट में ज्यादा आवंटन चाहिए। इंडस्ट्री चाहती है कि उत्पादन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी दी जाए। साथ ही, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स आ सकते हैं। इससे भारत दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा उत्पादक बन सकता है और विदेशी मुद्रा कमा सकता है।

रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना भी एक बड़ी उम्मीद है। घरों और इमारतों पर सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल कम होता है और पर्यावरण का बचाव होता है। बजट में रूफटॉप सोलर के लिए ज्यादा सब्सिडी या आसान लोन स्कीम्स आ सकती हैं। साथ ही, छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए टैक्स ब्रेक्स मिल सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर एनर्जी फैलेगी और किसानों को फायदा होगा, जैसे सोलर पंप और इरिगेशन सिस्टम।

बजट से क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। सरकार पिछले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, लेकिन अब कैपेसिटी एडिशन से आगे बढ़कर स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ग्रिड रिफॉर्म्स जरूरी हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपग्रेड। साथ ही, क्लीन एनर्जी फंड्स बढ़ाए जा सकते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।

एक और महत्वपूर्ण उम्मीद है कि बजट में ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते लोन देने के लिए इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। साथ ही, कार्बन टैक्स या ग्रीन बॉन्ड्स जैसी स्कीम्स आ सकती हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स से दूर जाने में मदद करेंगी। इससे विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में ग्रीन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है।

ग्रीन एनर्जी क्षेत्र को उम्मीद है कि बजट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन फ्यूल्स पर ज्यादा जोर होगा। उदाहरण के लिए, बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट। इससे प्रदूषण कम होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। साथ ही, आरएनडी पर ज्यादा बजट से नई इनोवेशंस आएंगी, जैसे एडवांस्ड सोलर सेल्स या विंड टरबाइन्स। इन सब उम्मीदों से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में तेजी आएगी लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगे इक्विपमेंट और ग्रिड कनेक्टिविटी। बजट अगर इन पर फोकस करे तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को आसानी से हासिल कर सकता है।

धर्मेंद्र प्रधान जो सच स्वीकारना नहीं चाह रहे!

– डॉ. मयंक चतुर्वेदी

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 ने देश की उच शिक्षा व्यवस्था को गंभीर असमंजस में डाल दिया है। सरकार इसे समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है, किंतु विश्वविद्यालय परिसरों में इसका असर इसके ठीक उलट दिखाई दे रहा है। वस्तुत- देश के अनेक हिस्सों में छात्र, शिक्षक और शैक्षणिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के जेएनयू और डीयू में कक्षाओं का बहिष्कार, मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में धरना, भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन घेराव जैसे अनेक विरोध देशभर में जनवरी 2026 से तेज हो चुके हैं। अब तक लाखों छात्र सड़क पर आकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, साफ समझ आ रहा है कि यह असंतोष प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 नियमों की एकतरफा भाषा और संरचना का परिणाम है। जब विरोध तेज हुआ और राजनीतिक दबाव बढ़ा, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए। 27 जनवरी को दिए बयान में उन्होंने कहा, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। न तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, न केंद्र या राय सरकार किसी कानून का दुरुपयोग होने देगी। पूरी व्यवस्था संविधान के दायरे में रहेगी। सुनने में यह बयान संतुलित लगता है, लेकिन समस्या यह है कि यह उस नियम से मेल नहीं खाता जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मंत्री का आश्वासन कागजी है क्योंकि नियम 3(सी) सामान्य वर्ग को असुरक्षित छोड़ देता है।

यूजीसी नियम- सतही समानता, गहरा पक्षपात

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में समानता समिति और समानता दस्ता का गठन अनिवार्य है। 24×7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। जाति आधारित भेदभाव पर त्वरित कार्रवाई, उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द या अनुदान रोकने की सजा- ये प्रावधान कागजों पर प्रभावी लगते हैं। किंतु वास्तविक विवाद नियम 3(सी) से उत्पन्न होता है। इसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित है।

यदि इन वर्गों का कोई छात्र सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक पर आरोप लगाएगा तो शिकायत प्राइमा फेसी अपराध मानी जाएगी। 24 घंटे में जांच, तत्काल निलंबन संभव। लेकिन उल्टा होने पर सामान्य वर्ग का ब्राह्मण, क्षत्रीय, कायस्थ, वैश्य या अन्य छात्र जातिगत अपमान का शिकार होता है तो उसके लिए यहां कोई स्पष्ट संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

तथ्य प्रमाण- यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अधिसूचना (राजपत्र अधिसूचना 2026/एचई/12) के पृष्ठ 5 पर नियम 3(सी) स्पष्ट लिखा है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के विरुद्ध भेदभाव में मौखिक अपमान, सामाजिक बहिष्कार शामिल...। सामान्य वर्ग का जिक्र शून्य। सर्वोच न्यायालय में दायर याचिका (रिट याचिका (सिविल) 2026/45, अभिषेक सिंह बनाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) ने ठीक यही उद्धृत कर कहा कि यह अनुछेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है। याचिका में मांग है कि परिभाषा सभी वर्गों के लिए हो।

इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक परिणाम उच शिक्षा में आरोप की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बिना ठोस प्रमाण सिर्फ शिकायत पर निलंबन। सामान्य वर्ग के लिए अपील तंत्र पूरी तरह कमजोर दिखता है या कहें, है ही नहीं तो कुछ गलत नहीं होगा । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े 2025 के अनुसार, परिसरों में जातिगत शिकायतों के मामलों में दुरुपयोग सिद्ध हुआ, जोकि सामान्य वर्ग के खिलाफ थे।

उदाहरण 1- आईआईटी कानपुर (2024)- अनुसूचित जाति छात्र ने ब्राह्मण पीएचडी छात्र पर सवर्ण अहंकार का आरोप लगाया। बिना जांच निलंबन कर दिया गया; न्यायालय ने बाद में बरी किया, किंतु जब तक उस छात्र के दो साल बर्बाद हो चुके थे, मानसिक प्रताड़ना, आर्थकि हानि के साथ पूरा परिवार दो वर्ष की न्याय की आस में न्यायालय, पुलिस प्रशासन और आईआईटी कानपुर के चक्कर लगाता रहा।

उदाहरण 2- जेएनयू (2022)- अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र की सामान्य वर्ग प्रोफेसर पर शिकायत पर विभागीय जांच हुई लेकिन उल्टा केस खारिज, प्रोफेसर साहब की कोई गलती नहीं पाई गई।

उदाहरण 3- आईआईएम बैंगलोर (2023)- एससी छात्र ने जनरल कैटेगरी छात्र पर जातिवादी होने का आरोप लगाया; ग्रुप प्रोजेक्ट से हटाया गया, बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि लगाया गया आरोप झूठा है।

उदाहरण 4- एआईआईएमएस दिल्ली (2024)- एसटी छात्र की सामान्य वर्ग इंटर्न पर भेदभाव शिकायत; होस्टल से निकाला, जांच हुई तो सामान्य वर्ग का छात्र निर्दोष सिद्ध हुआ।

उदाहरण 5- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (2025)- सामान्य वर्ग छात्र शिवम सोनकर को आरक्षण सीट न देने के नाम पर एससी संगठनों ने घेरा; दाखिला रुका। भोपाल एमएएनआईटी (2025)- एसटी छात्र ने जनरल छात्र को धमकाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोहिणी हत्याकांड (केरल विश्वविद्यालय, 2024) याद करें- सामान्य वर्ग लड़की को अनुसूचित जाति छात्रों ने जाति आधारित प्रताड़ना दी, लेकिन सुरक्षा अभाव में न्याय न मिला।

इस प्रकार के अनेक प्रकरण हैं, जिनमें जो पीड़ित पक्ष था, वही जांच या न्यायालय से आरोपी सिद्ध हुआ, किंतु जब तक ये जांच चली सामान्य वर्ग के छात्र को चहुंओर से सिर्फ अपमान ही सहना पड़ा है। जो शिकायत कर्ता था अथवा जो पीड़ित था, पता चला कि उसके एससी-एसटी होने के कारण से उसके जूठे पाए जाने के बाद भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये न्याय का मजाक नहीं है

संविधान का अनुछेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता देता है। अनुछेद 15(1) सभी नागरिकों के लिए जाति आधारित भेदभाव निषिद्ध करता है। सर्वोच न्यायालय के इंदिरा साहनी फैसले (1992) ने आरक्षण को सामाजिक न्याय कहा, लेकिन रिवर्स भेदभाव की मनाही की। यह नियम उसी का उल्लंघन है। अनुछेद 21 (जीवन का अधिकार) सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करता है। किंतु यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसे यहां तोड़ रहा है।

शिक्षा परिसर विचार-विमर्श का स्थान होना चाहिए, न कि डर का। यह नियम छात्रों को जातियों में बांटेगा। यह सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान का बयान तब तक अधूरा है जब तक नियम 3(सी) में सभी वर्गों को शामिल न किया जाए। सरकार को अधिसूचना वापस लेनी चाहिए या तटस्थ जांच तंत्र जोड़ना चाहिए। जूठी शिकायत पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। सर्वोच न्यायालय की निगरानी तो है, लेकिन स्थगन आदेश लगे बिना दुरुपयोग रुकेगा नहीं, यह तय है, इस बात को तो स्वयं धर्मेंद्र प्रधान को भी समझना चाहिए।

वैसे धर्मेंद्र प्रधान की पृष्ठभूमि छात्र नेता की रही है, वे लम्बे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यरत रहे हैं, एक जिला इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पदाधिकारी रहकर उन्होंने छात्रों की समस्याओं को नजदीक से जाना और उन समस्याओं के समाधान के लिए सतत संघर्ष किया है,

इसलिए आज उनके न्याय की आस है। देखा जाए तो यह जो नियम आया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसे आना ही नहीं चाहिए था, किंतु यदि सरकार को इतना ही जरूरी लगता है तो शिक्षा के स्तर पर जो समानता का नारा दिया जाता है, कम से कम इस नियम में उसी का पालन होता। अंत में यही कि न्याय सबके लिए होना चाहिए। अन्यथा, उच शिक्षा का भविष्य खतरे में है। सरकार सच स्वीकारे कि उससे गलती हुई, अब इसमें सुधार जितना शीघ्र हो उतना जल्दी करे, अन्यथा देश भर में यूजीसी द्वारा अधिसूचित उच शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 के विरोध में आंदोलन और तेज होंगे। जो कहीं से भी किसी के हित में नहीं हैं।

जोस बटलर बने 400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी

एजेंसी

कोलंबो। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोस बटलर ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 मैच खेलने वाले इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने यह मुकाम कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान हासिल किया। 35 वर्षीय बटलर इस मामले में अब केवल दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन से पीछे हैं। एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए तीनों प्रारूपों में कुल 401 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और वह देश की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व क्रिकेट के महानतम सीमर्स में शुमार एंडरसन ने अपने करियर में कुल 991 विकेट हासिल किए। जोस बटलर के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें, तो उन्होंने अब तक 12,291 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में बटलर ने 57 मैचों की 100 पारियों में 2,907 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका औसत 31.94 का रहा है, जिसमें दो शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में बटलर ने 198 मैचों की 171 पारियों में 5,515 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 39.11 का रहा है और उन्होंने 11 शतक व 29 अर्धशतक जड़े हैं।

ग्लेन मैक्सवेल ने मेलबर्न स्टार्स के साथ दो साल का नया करार किया

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग (बीबीएल) की फ्रेंचाइज़ी मेलबर्न स्टार्स के साथ अगले दो वर्षों के लिए दोबारा करार कर लिया है। क्लब ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बीबीएल के दूसरे सीजन से मेलबर्न स्टार्स से जुड़े मैक्सवेल अब तक टीम के लिए 123 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3,193 रन बनाए हैं। हरे रंग की जर्सी में उनका योगदान उन्हें लीग के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल करता है। मैक्सवेल बीबीएल इतिहास के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। हालांकि हालिया सीजन मैक्सवेल के लिए निराशाजनक रहा, जहां उन्होंने आठ पारियों में सिर्फ 76 रन बनाए और दो विकेट ही हासिल कर सके। 37 वर्षीय मैक्सवेल का बीबीएल 15 के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था लेकिन उन्होंने स्टार्स के साथ बने रहने का फैसला आसान बताया। मैक्सवेल ने कहा, 'मेलबर्न स्टार्स मेरे क्रिकेट करियर का बड़ा हिस्सा रहा है और मैं इस टीम की सफलता को लेकर बेहद जुनूनी हूं। मुझे लगता है कि मौजूदा टीम कुछ खास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले दो सीजन में हम खिताब के प्रबल दावेदार होंगे।

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज दौरा, खेलेगी छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज़

कोलंबो। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम फरवरी के आखिर से मार्च की शुरुआत तक वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज़ खेली जाएगी। इस दौरे में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले शामिल हैं, जो 20 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होंगे। सीरीज़ के सभी मुकाबले ग्रेनेडा के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज़ की शुरुआत 20 फरवरी को होगी, जबकि शेष दो मैच 22 और 25 फरवरी को खेले जाएंगे। इसके बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आगाज़ 28 फरवरी से होगा, वहीं दूसरे और तीसरे टी20 मैच क्रमशः 1 और 3 मार्च को खेले जाएंगे। टी20 सीरीज़ को खास अहमियत दी जा रही है, क्योंकि दोनों टीमें इस साल के अंत में इंग्लैंड में होने वाले 2026 महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों को धार देने उतरेंगी। वेस्टइंडीज और श्रीलंका को ग्रुप-2 में रखा गया है, जहां उनके साथ इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और दो क्वालीफायर टीमें भी शामिल होंगी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'श्रीलंका की राष्ट्रीय महिला टीम फरवरी-मार्च 2026 के दौरान वेस्टइंडीज का दौरा करेगी, जहां वह तीन मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ खेलेगी। दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज़ से होगी, जिसके बाद टी20 मुकाबले ग्रेनेडा में आयोजित किए जाएंगे। '

आईसीसी टी20 रैंकिंग: अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बरकरार, सूर्यकुमार यादव की लंबी छलांग

नई दिल्ली । आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले तीन टी20 मैचों में खेली 2 अर्धशतकीय पारियों के दम पर सूर्यकुमार यादव की एंट्री शीर्ष दस बल्लेबाजों में हो गई है। साल 2025 में बतौर बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे सूर्यकुमार यादव टी20 के शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हो गए थे। 2026 की शुरुआत भारतीय कप्तान के लिए बेहतरीन रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीन मैचों में 2 अर्धशतक की बदौलत उन्होंने 171 रन बनाए हैं। पिछले दोनों मैचों में वह नाबाद रहे। उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रहा है। तीन मैचों में किए दमदार प्रदर्शन की बदौलत सूर्यकुमार यादव ने पांच स्थान की छलांग लगाते हुए सातवां स्थान हासिल कर लिया है। शीर्ष दस बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो भारत के अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे, भारत के तिलक वर्मा तीसरे, इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पांचवें नंबर पर हैं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन: रयबाकिना ने स्वियातेक को चौंकाया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

मेलबर्न। पांचवीं वरीयता प्राप्त एलेना रयबाकिना ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक को 7-5, 6-1 से शिकस्त दी।

मेलबर्न पार्क में खेले गए इस मुकाबले में पहला सेट कड़ा रहा, लेकिन दूसरे सेट में रयबाकिना ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए जीत अपने नाम की। 28 वर्षीय रयबाकिना पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की दौड़ में हैं और अब सेमीफाइनल में उनका सामना जेसिका पेगुला या अमांडा अनीसिमोवा से होगा। मैच के बाद रयबाकिना ने कहा, 'इस जीत से

बहुत खुश हूं। हम एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह जानते हैं और मेरी कोशिश आक्रामक बने रहने की थी। पहले सेट में हम दोनों की पहली सर्विस ज्यादा प्रभावी नहीं थी, इसलिए हम दूसरी सर्विस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे सेट में मैंने ज्यादा खुलकर खेला, सर्विस बेहतर रही और यही फर्क पड़ा।

' मैच की शुरुआत स्वियातेक ने तेज़ की और पहले ही गेम में रयबाकिना की सर्विस तोड़ दी, लेकिन वह इस बढ़त को कायम नहीं रख सकीं और तुरंत ही ब्रेक वापस गंवा बैठीं। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बचाए रखीं। पहले सेट के अंतिम गेम में स्वियातेक की एक बड़ी चूक का फायदा उठाते हुए रयबाकिना ने सेट अपने नाम कर लिया, जिसे जीतने में करीब एक घंटा लगा। दूसरे सेट में रयबाकिना ने स्वियातेक की सर्विस से जुड़ी परेशानियों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तेज़ और सटीक फोरहैंड विनर लगाकर ब्रेक हासिल किया।

सेट के अंतिम हिस्से में एक करीबी लाइन कॉल को लेकर स्वियातेक असहज नजर आईं, जिसका फायदा उठाते हुए रयबाकिना ने एक और ब्रेक लिया और आराम से सर्विस होल्ड कर मुकाबला जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ एलेना रयबाकिना ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है और अब उनकी नजर फाइनल में प्रवेश करने पर होगी।

दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स को 6-3 से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में बनाई जगह

एजेंसी

नोएडा। प्रो रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) 2026 में दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स को नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 6-3 से मात देकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखीं। दिल्ली को इस जीत के दो अंक मिले और टीम अब चार मैचों में चार अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई। दिल्ली की जीत में तुरान बायरामोव, अंजली, अनास्तासिया अल्पयेवा, कार्ला गोदिनेज़ गोंज़ालेज़, कप्तान सुजीत कलकल और रोनक ने अहम भूमिका निभाई। टाइगर्स ऑफ मुंबई के लिए ज्योति सिहाग, मुकुल दहिया और अंतिम बाउट में मिली फॉरफिट से ही अंक जुटे, लेकिन टीम बिना कोई टीम जीत दर्ज किए टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

मुकाबले के दौरान अनास्तासिया अल्पयेवा को प्लेयर ऑफ द मैच और ज्योति सिहाग को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दिल्ली ने मैच की शुरूआत 74 किग्रा पुरुष वर्ग में तुरान बायरामोव की जीत से की। इसके बाद 62 किग्रा महिला वर्ग में अंजली और 76 किग्रा महिला वर्ग में अनास्तासिया अल्पयेवा ने जीत दर्ज कर स्कोरलाइन 3-0 कर दी। 57 किग्रा महिला वर्ग में कार्ला गोदिनेज़ गोंज़ालेज़ और 65 किग्रा पुरुष वर्ग में कप्तान सुजीत कलकल की जीत से दिल्ली ने बढ़त 5-0 तक बढ़ा दी। टाइगर्स ऑफ मुंबई ने 53 किग्रा महिला वर्ग में ज्योति सिहाग और 86 किग्रा पुरुष वर्ग में मुकुल दहिया की जीत से वापसी की, लेकिन अंतिम 125 किग्रा हेवीवेट पुरुष वर्ग में रोनक की जीत ने दिल्ली के लिए मैच सील कर दिया।

इथियोपिया के धावक ने जीती बलिया की मैराथन दौड़

एजेंसी

बलिया। बलिया में हुई बाबू मैनेजर सिंह मैराथन प्रतियोगिता इथियोपिया के धावक फिरोनशा के नाम रही। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन का उद्घाटन प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव ने किया। बलिया के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम से बैरिया स्थित बाबू मैनेजर सिंह स्मारक तक 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान इथियोपिया के धावक फिरोनशा ने हासिल किया।

जबकि मुजफ्फरपुर के अक्षय कुमार द्वितीय, दिल्ली के अमरेश प्रजापति तृतीय, सतना (मध्यप्रदेश) के अभिषेक सोनी चौथे और मुजफ्फरपुर के आकाश कुमार पांचवें स्थान पर रहे। प्रथम स्थान हासिल करने वाले फिरोनशा को दो लाख 25 हजार का इनाम दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि मैराथन जैसे आयोजन युवाओं में खेल भावना,

अनुशासन एवं स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हैं। खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों से फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों को नई ऊर्जा मिलती है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व मंत्री नारद राय, महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुड्डू राय, जिला मंत्री अरुण सिंह बंटू, कृष्णा पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

कोग्नीवेरा कप 2026: जिंदल बेदला ने चांदना पोलो को 9.5-5 से हराया

एजेंसी

जयपुर। कोग्नीवेरा कप 2026 के तहत जयपुर में बुधवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में जिंदल बेदला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चांदना पोलो को 9.5-5 से पराजित किया। इस जीत के साथ जिंदल बेदला ने मौजूदा सत्र में अपनी विजयी लय को और मजबूत किया।

हैंडिकैप नियम के तहत जिंदल बेदला ने मैच की शुरुआत 0.5 अंक की बढ़त के साथ की। शुरुआती चक्कर में दोनों टीमों ने तेज़ खेल दिखाते हुए एक-दूसरे की रक्षा पंक्तियों को भेदने की कोशिश की। हालांकि, जल्द ही जिंदल बेदला ने मैच पर पकड़ बना ली। सिद्धांत शर्मा और राव हिम्मत सिंह बेदला के बेहतरीन खेल की बदौलत जिंदल बेदला ने दूसरे चक्कर के अंत तक मजबूत बढ़त हासिल कर ली। सिद्धांत शर्मा ने लगातार तीन गोल दागते हुए टीम की बढ़त को 3.5 गोल तक पहुंचाया। दूसरे चक्कर के अंत में स्कोर 6.5-3 जिंदल बेदला के पक्ष में रहा। अंतिम चक्कर में भी जिंदल बेदला का दबदबा बरकरार रहा। सिद्धांत शर्मा ने दो और गोल करते हुए मुकाबले को पूरी तरह अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया और किसी भी संभावित उलटफेर की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैच में सिद्धांत शर्मा ने कुल छह गोल किए, जबकि राव हिम्मत सिंह बेदला ने दो गोल दागे। सिमरन शेरगिल ने भी एक गोल कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। यह जीत हाल ही में राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप में मिली सफलता के बाद आई है, जिससे साफ है कि इस सत्र में जयपुर पोलो सर्किट में जिंदल बेदला सबसे मजबूत टीम के रूप में उभर रही है। टीम अब ऐतिहासिक सात फुट ऊंची कोग्नीवेरा ट्रॉफी जीतने की ओर मजबूती से बढ़ रही है।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी20 में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया

एजेंसी

पर्ल। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार देर रात (स्थानीय समयानुसार) पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जॉर्ज लिंडे की शानदार गेंदबाजी और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम ने यह जीत आसानी से दर्ज की।

पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जॉर्ज लिंडे (3/25) के नेतृत्व में अनुशासित प्रदर्शन किया। केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश ने भी दो-दो विकेट चटकाए, जिससे वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। मेहमान टीम के लिए शिमरोन हेटमायर ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि रोवमैन पॉवेल 29 रन बनाकर नाबाद रहे। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। कप्तान एडेन मार्करम ने 47 गेंदों

पर नाबाद 86 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और नौ चौके शामिल थे। उन्हें युवा ओपनर ल्हुआन-ड्रे प्रिटोरियस (28 गेंदों पर 44 रन) और ryan रिकेल्टन (32 गेंदों पर नाबाद 40 रन) का अच्छा साथ मिला। दक्षिण अफ्रीका ने 17.5 ओवर में ही 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्करम और प्रिटोरियस ने पहले विकेट के लिए आठ ओवर में 83 रन जोड़कर मैच को शुरुआती चरण में ही वेस्टइंडीज की पकड़ से बाहर कर दिया। पावरप्ले के आखिरी दो ओवरों में 29 रन बटोरते हुए दक्षिण अफ्रीका ने बिना विकेट गंवाए छह ओवर में 68 रन बना लिए। प्रिटोरियस के आउट होने के बाद भी मार्करम ने रनगति बनाए रखी और कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को आसान जीत दिलाई। वेस्टइंडीज के लिए यह दिन गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों में निराशाजनक रहा। विशेषकर अकील हुसैन का दिन खराब रहा, जिन्होंने मार्करम का आसान कैच छोड़ा और तीन ओवर में 31 रन लुटा दिए। मार्करम ने अंत में जेसन होल्डर की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर जीत पर मुहर लगा दी। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्य ओवरों में लड़खड़ा गई।

रोहित शर्मा ने भारत की व्हाइट-बॉल क्रांति की अगुवाई करके टीम को नई पहचान दी : राहुल द्रविड़

एजेंसी

बेंगलुरु। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि रोहित शर्मा ने भारत की व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बदलाव की प्रक्रिया का नेतृत्व करके टीम को एक नई सोच व आक्रामक पहचान दी।द्रविड़ ने यह बातें लेखक आर. कौशिक की पुस्तक 'द राइज ऑफ द हिटमैन' के विमोचन समारोह के दौरान कहीं, जिसका आयोजन केएससीए में जैन स्पोर्ट्स ने किया। द्रविड़ ने आगामी आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप को लेकर भारत को प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने टी-20 क्रिकेट में लगभग 80 प्रतिशत सफलता दर हासिल की है, जो इस फॉर्मेट में असाधारण है। भारत निश्चित रूप से पसंदीदा के तौर पर उतरेगा और सेमीफाइनल तक पहुंचेगा, लेकिन टी-20 में नतीजा उसी दिन बेहतर खेलने वाली टीम तय करती है। रोहित शर्मा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए द्रविड़ ने कहा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी। रन रेट बढ़ रहे थे, जोखिम लेना जरूरी हो गया था और हमें खुद को ढालना था। रोहित ने यह जिम्मेदारी खुद ली।

उन्होंने उदाहरण पेश किया कि टीम का कप्तान खुद आगे बढ़कर टेम्पो सेट करे, भले ही इससे व्यक्तिगत आंकड़ों पर असर पड़े। उन्होंने आगे कहा कि रोहित की नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि कप्तान बनने के बाद भी टीम को कभी नहीं लगा कि वह बदले हैं। यह गुण बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है।

गुजरात जायंट्स से हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स को झटका, स्लो ओवर-रेट के चलते जेमिमा रोड्रिग्स पर जुर्माना

एजेंसी

वडोदरा। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्लो ओवर-रेट के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह मैच बीसीए स्टेडियम, वडोदरा में खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में तीन रन से हार का सामना करना पड़ा। जेमिमा पर यह उनका पहला ओवर-रेट अपराध होने के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पिछले सप्ताह लगातार दो जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन गुजरात जायंट्स के खिलाफ मिली इस करीबी हार से उसे झटका लगा है। इस हार के बाद अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है।मैच में

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 15 रन खर्च किए, जिससे जायंट्स एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। हालांकि, सातवें विकेट के लिए हुई अहम साझेदारी ने दिल्ली को मुकाबले में वापस ला दिया और मैच को आखिरी ओवर तक खींच ले गई। लेकिन 17वें ओवर में महंगे साबित होने के बाद, सोफी डिवाइन ने 20वें ओवर में शानदार वापसी की। उन्होंने दबाव में संयम दिखाते हुए रन रोकने में सफलता हासिल की और अपनी टीम को मामूली अंतर से जीत दिलाई। इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में पहुंचना अब उनके आखिरी लीग मैच पर निर्भर करेगा। दिल्ली कैपिटल्स अपना अंतिम मुकाबला 1 फरवरी को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ खेलेगी, जो उनके लिए 'करो या मरो' जैसा साबित हो सकता है।

गुजरात के खिलाफ जुझारू पारी के बाद बोलीं निकी प्रसाद- ये परिस्थितियां मेरे लिए सीखने के पल हैं

एजेंसी

वडोदरा। जेएसडब्ल्यू और जीएमआर की सह-मालिकाना हक वाली दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम बीसीए स्टेडियम, कोटांबी में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स के खिलाफ तीन रन से हार गई। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में 20 वर्षीय युवा बल्लेबाज़ निकी प्रसाद ने दबाव भरी स्थिति में शानदार जुझारूपन दिखाया। टीम के 100 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरीं निकी ने मात्र 25 गेंदों में 47 रनों की निडर पारी खेली। उन्होंने स्नेह राणा के साथ सिर्फ 31 गेंदों में 70 रनों की अहम साझेदारी कर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया। हालांकि अंतिम ओवर में सोफी डिवाइन ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए आठ रनों का बचाव किया और गुजरात जायंट्स को जीत दिलाई। इससे पहले गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स की ओर से श्रेया चरणी सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहीं, जिन्होंने 31 रन देकर 4 विकेट झटके और मध्य ओवरों में रन गति पर काफी हद तक लगाम लगाई। मैच के बाद अपनी पारी पर बात करते हुए निकी प्रसाद ने कहा, 'जब मैं बल्लेबाज़ी करने आई, तब स्थिति काफी मुश्किल थी। लेकिन मेरे दिमाग में साफ था कि अगर मैं क्रीज़ पर टिके रहूं और रन गति बनाए रखूं, तो हम मैच में बने रह सकते हैं। स्नेह के आते ही जिस तरह उन्होंने चौके लगाए, उससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। हम दोनों की कोशिश 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार बनाए रखने की थी। ' अपनी बल्लेबाज़ी रणनीति पर बोलते हुए निकी ने कहा, 'हमने जल्दी समझ लिया था कि गेंदबाज़ थोड़ी धीमी और छोटी गेंदें कर रहे हैं, इसलिए मैंने गैप्स में खेलने और हवा में शॉट लगाने की कोशिश की। जैसे ही गेंद ज़मीन पर लगती थी, वह तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी। ' करीबी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'इतने करीब आकर हारना निराशाजनक है, लेकिन मेरे लिए ये परिस्थितियां सीखने के पल हैं। मैं और मेहनत करूंगी ताकि अगली बार ऐसी स्थिति में टीम को जीत दिला सकूं। '

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 एलएंडटी मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए 125के सीरीज की ट्रॉफी का किया अनावरण

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2026 एलएंडटी मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए 125के सीरीज की ट्रॉफी का औपचारिक अनावरण किया। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट 02 से 08 फरवरी 2026 तक मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन (एमएसएलटीए) परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निवास पर आयोजित इस समारोह में टूर्नामेंट की संरक्षक अमृता फडणवीस, एलएंडटी के वरिष्ठ अधिकारी एस.वी. देसाई और सुमीत चटर्जी, एमएसएलटीए के अध्यक्ष प्रशांत सुतार, चेयरमैन भरत ओझा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इसके अलावा उभरती भारतीय टेनिस खिलाड़ी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की कांस्य पदक विजेता वैष्णवी आदकर तथा भारतीय फेड कप कोच राधिका तुलपुले-कानिटकर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई ओपन का पांचवां संस्करण महाराष्ट्र और देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे।

साई खेल विज्ञान प्रभाग ने शूटिंग और तीरंदाजी के कोचों के लिए शुरू की विशेष कार्यशाला

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेल विज्ञान प्रभाग ने शूटिंग और तीरंदाजी से जुड़े साई कोचों के लिए चार दिवसीय विशेष खेल विज्ञान कार्यशाला सोमवार से इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित साई खेल विज्ञान प्रभाग में शुरू की। इस अवसर पर खेल सचिव एवं महानिदेशक, साई, हरि रंजन राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उद्घाटन संबोधन में दैनिक प्रशिक्षण वातावरण में खेल विज्ञान के गहरे एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। राव ने कहा, 'मंत्रालय और सरकार खेल विज्ञान पहलों को हर संभव समर्थन देंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि हम सोच-समझकर निवेश करें और परिणाम देने के लिए खेल विज्ञान का सटीक उपयोग करें। खासकर उन खेलों में जहां मामूली सुधार भी पदक और भागीदारी के बीच अंतर पैदा कर सकता है, वहां खेल विज्ञान की भूमिका बेहद अहम है। '

यह कार्यशाला दिसंबर में शुरू हुई कोच सेंसिटाइजेशन कार्यशालाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, और अब इसमें शूटिंग व तीरंदाजी को शामिल किया गया है।

राव ने आगे कहा, 'खेल विज्ञान कुशल प्रशिक्षण, चोटों की रोकथाम और खिलाड़ियों के लंबे करियर को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे खिलाड़ियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होता है। हम देशभर में खेल विज्ञान समर्थन को और मजबूत करेंगे, इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और राष्ट्रीय शिविरों व उत्कृष्टता केंद्रों में एथलीट सहायता प्रणालियों को सशक्त किया जाएगा। '

इस कार्यशाला में कोचों के साथ खेल वैज्ञानिक, मेडिकल विशेषज्ञ और परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट एक मंच पर आए हैं, ताकि पारंपरिक कोचिंग अनुभव को वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित आधुनिक तरीकों से जोड़ा जा सके। यह पहल युवा मामले और खेल मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत विभिन्न खेल श्रेणियों–कॉम्बैट, एंड्योरेंस, टीम और सटीक खेलों–में कोचों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साई के खेल विज्ञान प्रभाग के निदेशक-सह-प्रमुख ब्रिगेडियर (डॉ.) बिभु कल्याण नायक ने कहा, 'केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और खेल सचिव लगातार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि कोचों को खेल विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित किया जाए, ताकि इन सिद्धांतों को रोज़मर्रा के प्रशिक्षण में लागू किया जा सके। ऐसे केंद्रित प्रयास भारत की पदक संभावनाओं को मज़बूती देंगे। हमारा दृष्टिकोण एथलीट-केंद्रित, कोच-नेतृत्व वाला और खेल विज्ञान से समर्थित है। ' सटीक खेलों के लिए आयोजित यह विशेष कार्यशाला शूटिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रदर्शन आधारित दृष्टिकोण को मज़बूत कर रही है, जहां मामूली सुधार भी पदक तय कर सकता है। कार्यक्रम के तहत बायोमैकेनिक्स, कंडीशनिंग और स्थिरता प्रशिक्षण के जरिए पोश्चर कंट्रोल, निरंतरता और चोटों से बचाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोचों को मूवमेंट एनालिसिस और कोर-स्टेबिलिटी आधारित कंडीशनिंग के व्यावहारिक प्रयोग भी सिखाए जा रहे हैं। सत्रों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कोच वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीधे दैनिक प्रशिक्षण में उतार सकें, जिससे तकनीकी दक्षता बढ़े और चोटों का जोखिम कम हो। कार्यशाला में फिज़ियोलॉजी, रिकवरी साइंस, खेल मनोविज्ञान और खेल चिकित्सा जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। कोचों को पोषण, हाइड्रेशन, चोट रोकथाम, योग आधारित रिकवरी और दीर्घकालिक एथलीट स्वास्थ्य पर आधारित मॉड्यूल्स के साथ-साथ एकाग्रता, दबाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित खेल मनोविज्ञान सत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दावोस में टीम योगी की बड़ी उपलब्धि, मिले लगभग तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

एजेंसी
लखनऊ। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए लगभग तीन लाख करोड़ (2.92 करोड़ से अधिक) के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) सुनिश्चित किए हैं। सम्मेलन से लौटने के बाद लोक भवन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और निवेश उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाला बताया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 119 उच्च स्तरीय बैठकें कीं, जिनमें 55-56 प्रमुख वैश्विक कंपनियां शामिल रहीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, फार्मा, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में 31 एमओयू संपन्न हुए। इन सभी एमओयू के माध्यम से कुल प्रस्तावित निवेश 2.92 लाख करोड़ से अधिक का है, जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।वित्त मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव नीदरलैंड की कंपनी 'एएम-ग्रीन' के साथ हुआ है। इस एमओयू के तहत ग्रेटर नोएडा में एआई आधारित एक गीगावॉट डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक लगभग 2.10 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना से न केवल प्रदेश में डिजिटल और तकनीकी क्रांति आएगी, बल्कि इससे जुड़े सहायक उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। इसके साथ ही, एएसएम टेक्नोलॉजी के साथ 200 करोड़ का एमओयू भी हुआ। वहीं, उबर द्वारा विस्तारित मोबिलिटी सहभागिता और संभावित जीसीसी की स्थापना में रुचि व्यक्त की गई। यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दावोस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एमओयू किए गए, जिनमें सोलर रूफटॉप एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज में 1000 करोड़, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट में 1100 करोड़, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एवं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में 10 हजार 500 करोड़, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क (तीन गीगावॉट सोलर सेल मॉड्यूल + 60 मेगावॉट सोलर प्लांट) में तीन हजार 800 करोड़ का एमओयू सम्मिलित है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर गैर-वित्तीय एमओयू तथा आईसी लिमिटेड द्वारा 500 मेगावाट कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आठ हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल रहे। वित्त मंत्री ने बताया कि रश्मि मेटालिक्स ने एक एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए चार हजार करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने को ऊर्जा संक्रमण में निरंतर हो निवेशः हरदीप पुरी

एजेंसी
गोवा/नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सुरक्षा, किफायत और दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण में निरंतर निवेश होना चाहिए। पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में यह बात कही। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और एडीएनओसी के प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर के मुख्य भाषणों और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के स्वागत भाषण के साथ हुआ। मंत्रालय के मुताबिक कार्यक्रम में वक्ताओं ने ऊर्जा संबंधी विषय पर संवाद को कार्यान्वयन में परिवर्तित करने और महत्वाकांक्षा को परिणामों में बदलने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में इस वैश्विक सम्मेलन की भूमिका दोहरायी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन भाषणों में वैश्विक स्तर पर व्यावहारिक, विस्तार योग्य और समावेशी समाधान प्रस्तुत करने वाले अग्रणी और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित किया गया। साथ ही, इस दौरान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और निवेश जुटाने पर विशेष रूप से बल दिया गया।

भारत-ईयू समझौताः भारतीय व्यापारियों, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी वैश्विक बढ़त

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्?त व्यापार समझौते (एफटीए) को देश की वैश्विक आर्थिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है, जिसके तहत भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। खंडेलवाल ने एक बयान में कहा कि यह समझौता भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा तथा भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से और अधिक मजबूती से जोड़ेगा। उन्होंने कहा, 'यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती आर्थिक मजबूती, नीति-स्थिरता और सुधार आधारित विकास का स्पष्ट प्रमाण है।' इस समझौते के प्रमुख लाभों को रेखांकित करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि भारत-ईयू समझौते से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा।

अडाणी समूह और एम्ब्रेयर भारत में क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र करेंगे स्थापित

नई दिल्ली। अडाणी समूह और ब्राजील की विमानन कंपनी एम्ब्रेयर भारत में क्षेत्रीय विमान निर्माण इकाई स्थापित करेंगी। रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बाद इस साझेदारी का ऐलान नई दिल्ली में किया गया। अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने नागर विमानन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू की मौजूदगी में एमओयू हुआ। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) भी स्थापित करेंगी। हालांकि, निवेश और प्रस्तावित सुविधा के स्थान से जुड़े विवरण साझा नहीं किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इस अवसर पर कहा कि एम्ब्रेयर और अडाणी ऑनलाइन के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारत के क्षेत्रीय परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत है। नायडू ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के उड़ान विजन से प्रेरित यह साझेदारी क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए एंड-टू-एंड स्वदेशी समाधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। घरेलू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ सेवाओं के लिए पार्टनरशिप 'मेक इन इंडिया' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी और वैश्विक एविएशन सप्लाई चेन में भारत के इंटीग्रेशन को मजबूत करेगी।

उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए ट्रेड डील से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। आज के कारोबार की मिली-जुली शुरुआत हुई थी। सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला था, जबकि निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ शुरुआत की थी। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण इन दोनों सूचकांकों की चाल में कमजोरी आ गई। पहले 15 मिनट के कारोबार के बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे शेयर बाजार की चाल में सुधार होने लगा। कारोबार के दौरान दिन के ज्यादातर समय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहा, लेकिन आखिरी घंटे में चौतरफा खरीदारी शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में जोरदार तेजी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.39 प्रतिशत और निफ्टी 0.51 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के दौरान बैंकिंग, मेटल और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही।

बजट की तैयारी अंतिम चरण में, सीतारमण ने पारंपरिक हलवा सेरेमनी में हिस्सा लिया

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। ये समारोह 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक है। वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा भी किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। हलवा सेरेमनी का ये समारोह रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जो वित्त मंत्रालय का पुराना पता है। वित्त मंत्री और उनकी टीम के अधिकतर सदस्य सितंबर, 2025 में प्रतिष्ठित और भव्य नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन स्थित आधुनिक केंद्रीय सचिवालय कार्यालय में स्थानांतरित हो गए थे। कर्तव्य भवन-1 स्थित नए परिसर में छापाखाना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सभी विभागों के सचिव और केंद्रीय बजट तैयारी में शामिल अन्य वरिष्ठ

अधिकारी भी मौजूद थे। पिछले पांच पूर्ण केंद्रीय बजट और एक अंतरिम बजट की तरह 2026-27 का पूर्ण केंद्रीय बजट भी कागज रहित यानी डिजिटल रूप में होगा।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में चौथा तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन शुरू

एजेंसी
झांसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 28 से 30 जनवरी 2026 तक चौथा राष्ट्रीय-सह-अंतरराष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन (जीसीएडब्ल्यूएस-2026) आयोजित किया जाएगा। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय 'सतत विकास, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुदृढ़ता हेतु स्वदेशी एवं अल्प उपयोगित बागवानी फसलों का उपयोग' रखा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ए.के. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश और विदेश से लगभग 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें किसान, वैज्ञानिक, शोधार्थी और नीति निर्माता शामिल होंगे। तीन दिनों के दौरान 10 सेशन आयोजित होंगे, जिनमें नीति, उद्योग और तकनीकी पहलुओं पर व्यापक चर्चाएं होंगी। सम्मेलन में प्रमुख अतिथि डॉ पंजाब सिंह (कुलाधिपति), डॉ एस.के. सिंह (उप महानिदेशक, बागवानी, आईसीएआर), डॉ बलराज सिंह सहित देश-विदेश के प्रतिष्ठित कृषि एवं बागवानी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सम्मेलन में स्वदेशी और अल्प उपयोगिता बागवानी फसलों के फसल सुधार, जैव विविधता संरक्षण, आधुनिक प्रजनन तकनीक, जलवायु-सहिष्णु और संरक्षित बागवानी, सटीक कृषि, रोग एवं कीट प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, विपणन, निर्यात और एफपीओ आधारित उद्यमिता पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को लाइफटाइम अचीवमेंट, युवा वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक, श्रेष्ठ शिक्षक और नेतृत्व उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।कुलपति डॉ ए. के. सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन किसानों की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और कृषि नवाचार आधारित उद्यमिता को नई दिशा देगा और कृषि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।उक्त प्रेस वार्ता में डॉ बलराज सिंह, डॉ मनीष श्रीवास्तव, गौरव शर्मा, एम.जे. डोबरियाल और प्रभात तिवारी सहित विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक कदमः भाजपा

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता सही मायनों में 'मदर ऑफ ऑल डील्स' है। इस समझौते से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी, सेवाओं का विस्तार होगा और भारतीय कंपनियों को यूरोप के बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ यह समझौता भारत-ईयू रिश्तों को नई ऊंचाई देगा और विकसित भारत के

लक्ष्य को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने समझौते को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे 200 करोड़ लोग व्यापार कर पाएंगे। इसका व्यापक प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समझौते से भारत में एमएसएमई, ऊर्जा क्षेत्र, पेट्रो-गैस, समुद्र मंथन, रक्षा क्षेत्र तथा निर्माणक्षेत्र, प्रत्येक सेक्टर में वैश्विक उन्नति में बहुत मदद मिलेगी। वस्त्र, उद्योग, आभूषण, चमड़ा उद्योग तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। शीघ्र ही व्यापार और उद्योग के दरवाजे भारत के लिए लगभग 50 से अधिक देशों में खुलेंगे अर्थात भारत में संपन्नता बढ़ेगी।

भारत-ईयू समझौता विकसित भारत की नींवः शिवराज

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है।

शिवराज ने पत्रकारों से कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद- जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर

आगे बढ़ रहा है। यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत की कृषि शक्ति आज विश्व के सामने है-भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है।

चौहान ने कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी कदम है।

उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज किसानों की कमर तोड़ देते हैं, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार एक सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट और सुरक्षित भविष्य मिल सके। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण आवश्यक है। इसी संकल्प के तहत 'विकसित भारत-जी-राम-जी अधिनियम' देश में लागू किया जा रहा है, जिससे गांव संपूर्ण विकसित ग्राम के रूप में उभर सकेंगे और ग्रामीण भारत विकास की मुखधारा में मजबूती से खड़ा होगा।

स्टॉक मार्केट मे शैडोफैक्स कमजोर लिस्टिंग, घाटे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी
नई दिल्ली। लॉजिस्टिक सर्विस देने वाली कंपनी शैडोफैक्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में कमजोर एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 124 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग करीब 9 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 113 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 112.60 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से इस शेयर ने कुछ हद तक रिकवरी भी की थी पहले दो घंटे का कारोबार होने के बाद 11:15 बजे कंपनी के शेयर बीएसई पर 116.35 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के लिवाली का सपोर्ट मिलने के बावजूद कंपनी के आईपीओ निवेशक 6.17 प्रतिशत के नुकसान में हैं। शैडोफैक्स का 1,907.27 करोड़ रुपये का आईपीओ 20 से 22 जनवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 2.86 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन चार गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.88 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.43 गुना और एम्प्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन 2.17 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 18,10,45,160 शेयर जारी किए गए हैं। इनमें 1,000 करोड़ रुपये के 8,06,45,161 नए शेयर और 907 करोड़ रुपये के 7,31,66,935 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसा का इस्तेमाल कंपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने, लीज पेमेंट करने, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

डाक विभाग का एसएसएल से समझौता, अब डाकघरों से मिलेगी पूंजी बाजार सेवाओं की सुविधा

एजेंसी
नई दिल्ली। डाक विभाग ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (एसएसएल) के साथ पूंजी बाजार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत आम लोगों को अब डाकघरों और डिजिटल माध्यमों से डिमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, आईपीओ में भाग लेने और अन्य निवेश विकल्पों का लाभ उठाने जैसी तमाम सहूलियतें मिलेंगी।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता नई दिल्ली स्थित डाक भवन में हुआ। इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा वित्तीय जागरूकता और निवेशक शिक्षा है। एसएसएल निवेशक शिक्षा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाएगा, जिसमें डाक

विभाग भी सहयोग करेगा। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के नए निवेशकों को समझाने पर जोर रहेगा। डाक सचिव वंदिता कौल ने कहा कि यह सहयोग वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 की सोच से जुड़ा है। डाक विभाग का डिजिटल नेटवर्क अब लोगों को सुरक्षित तरीके से पूंजी बाजार में भागीदारी करने में मदद करेगा। एसएसएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभात कुमार दुबे ने कहा कि उन्हें डाक विभाग के साथ जुड़कर खुशी है। एसएसएल पारदर्शी और नियंत्रित पूंजी बाजार सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और निवेशकों को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि डाक विभाग के पास देशभर में 1.65 लाख से अधिक डाकघर हैं, जिनमें ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी मजबूत नेटवर्क है। इस सहयोग का उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित और नियंत्रित पूंजी बाजार से जुड़ें। अब नागरिक पोस्ट ऑफिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एसएसएल की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें डिमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, आईपीओ में हिस्सा लेना और अन्य निवेश विकल्प शामिल होंगे।

डिजिलॉजिक सिस्टम्स ने निवेशकों को दिया झटका, कमजोर लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

एजेंसी
नई दिल्ली। डिफेंस और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिमुलेटर के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और सपोर्ट का काम करने वाली कंपनी डिजिलॉजिक सिस्टम्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को जोरदार झटका दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 104 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 83.20 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर थोड़ी देर बाद ही 79.05 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी को प्रति शेयर 24.95 रुपये यानी 23.99 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। डिजिलॉजिक सिस्टम्स का 81 करोड़ रुपये का आईपीओ 20 से 22 जनवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.10 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.42 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.08 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 2 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 77.88 लाख शेयर जारी किए गए हैं। इनमें 66 करोड़ रुपये के 63,08,400 नए शेयर जारी किए गए हैं, जबकि 10,89,600 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी नई फैसिलिटी का सेटअप करने, पुराने कर्ज का बोझ कम करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 2.18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

ऐतिहासिक निचले स्तर से उबरा रुपया, 22 पैसे मजबूत

एजेंसी
मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 91.68 रुपये का

बोला गया। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 32.50 पैसे टूटकर 91.9050 रुपये प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुई थी।

आज रुपये में शुरू से ही तेजी रही। यह 8.50 पैसे की बढ़त में 91.82 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। बीच कारोबार में यह ऊपर 91.63 रुपये और नीचे 91.90 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अंत में 22 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ। यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा से रुपया मजबूत हुआ है। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की नरमी से भी भारतीय मुद्रा को समर्थन मिला है।

यूरोपीय बाज़ार में तेजी से पैठ बनेगी भारतीय उत्पादों की : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

एजेंसी
नई दिल्ली।भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बनी सहमति को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताते हुए आज कहा कि इस समझौते के अमल के बाद भारत की यूरोपीय बाज़ारों में तेजी से पैठ बनेगी और वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था 300 खरब डॉलर पार कर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भारत यात्रा पर आये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच यहां हैदराबाद हाउस में हुई 16वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक के परिणामों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह कहा।

सबसे पहले विदेश सचिव ने बैठक के बारे में प्रारंभिक जानकारी देते हुए कहा कि आज, कोस्टा और वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री मोदी ने 16वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने प्रतिबंधित प्रारूप और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के नेताओं के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया। नेताओं के समक्ष कई प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया, जिनमें एक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के समापन पर संयुक्त घोषणा, दोनों पक्षों के बीच एक समान रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता और मानव संसाधनों की आवाजाही संबंधी सहयोग पर व्यापक ढांचे पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मानव संसाधनों की आवाजाही संबंधी सहयोग पर व्यापक ढांचे पर पहला समझौता है जिसे हम किसी भी भागीदार के साथ यूरोपीय संघ के स्तर पर संपन्न कर रहे हैं। यह समझौता, सुरक्षित, नियमित प्रवासन को सुगम और सुव्यवस्थित करेगा, कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा और अत्यधिक कुशल श्रमिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं एवं अल्पकालिक श्रमिकों की आवाजाही को आसान बनाएगा। इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण सहमतियां भी हुईं, जिनमें हाइड्रोजन पर एक संयुक्त कार्य बल और भारत-यूरोपीय संघ त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत परियोजनाओं की घोषणा शामिल है। वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-यूरोपीय संघ समझौते का नवीनीकरण; उन्नत ई-हस्ताक्षर, और मुहरों पर प्रशासनिक व्यवस्था; भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन; और आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग पर प्रशासनिक व्यवस्था और बहुत महत्वपूर्ण रूप से हरित हाइड्रोजन यूरोप के साथ भारत के सहयोग पर खोजपूर्ण वार्ता शुरू करना का निर्णय आदि। उन्होंने कहा कि हमने हरित हाइड्रोजन पर एक भारत-यूरोपीय संघ कार्यबल का भी गठन किया और कौशल गतिशीलता बढ़ाने और बातचीत शुरू करने के लिए भारत में एक यूरोपीय संघ पायलट कानूनी गेटवे कार्यालय की स्थापना की है। भारत-यूरोपीय संघ एफटीए पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ आज लगभग 65 खरब डॉलर मूल्य के सामान और लगभग 30 खरब डॉलर मूल्य की सेवाओं का आयात करता है। भारत इसमें बहुत छोटी भूमिका निभाता है। हमारा कुल निर्यात वर्तमान में यूरोप में आयात किए गए सामानों का लगभग 1.5फीसदी है और यूरोप में आयात की जाने वाली सेवाओं का मुश्किल से 2.5फीसदी है। अवसरों के इस बड़े पैमाने पर खुलने के साथ, यूरोपीय संघ ने कई नए क्षेत्रों को भी खोला है। भारत ने सेवा क्षेत्र में कई नए सेक्टर्स खोले हैं। हम सेवा क्षेत्र में एक बड़ा जोर देख सकते हैं। समुद्री उत्पादों पर, लगभग 94 प्रतिशत टैरिफ लाइनें और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लगभग पूरे मूल्य को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। कपड़ा, परिधान, घर की सजावट, साज-सज्जा जैसे क्षेत्र, जहां भारत के बहुत गंभीर श्रमसाध्य हित शामिल हैं, यूरोपीय बाजार का 100फीसदी पहले दिन से ही व्यापार के लिए खुला रहेगा।

ईयू की आतंकी सूची में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को शामिल करने की कोशिश पर ईरान नाराज, इतालवी राजदूत तलब

एजेंसी

तेहरान। ईरान ने यूरोपीय संघ की आतंकी सूची में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) को शामिल कराने की कोशिशों को लेकर इटली के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर तेहरान में इटली के राजदूत को तलब किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इटली के विदेश मंत्री से अपने 'अविवेकपूर्ण रवैये' को सुधारने की मांग की है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया, तो इसके 'गंभीर और विनाशकारी परिणाम' होंगे। ईरान का कहना है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स देश की आधिकारिक सैन्य संस्था है और उसे आतंकी संगठन के रूप में चिह्नित करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होगा। तेहरान ने इस कदम को राजनीतिक दबाव और शत्रुतापूर्ण नीति का हिस्सा बताया है। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में ईयू के कुछ सदस्य देशों द्वारा आईआरजीसी को आतंकी सूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है, जिस पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई है।

नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने पर विचार कर रहा श्रीलंका

कोलंबो। श्रीलंका की सरकार ऑनलाइन कंटेंट के हानिकारक प्रभावों से जुड़ी चिंताओं में वृद्धि के बीच सोशल मीडिया तक नाबालिग बच्चों की पहुंच सीमित करने पर विचार कर रही है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि के बाद विद्यार्थियों और नाबालिगों के सोशल मीडिया के उपयोग पर संभावित सीमाओं का पता लगाने के लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने का निर्णय जनसंचार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के तहत आएगा। एक बार नीति को अंतिम रूप देने के बाद, अधिकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। श्री वीरारत्ने ने कहा कि सरकार अभी तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है, लेकिन देश को सोशल मीडिया कंटेंट से नाबालिग बच्चों के दिमाग को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां नियंत्रण लागू करने के लिए स्थानीय दूरसंचार प्रदाताओं के साथ काम कर सकती हैं। श्री वीरारत्ने ने कहा कि इसी तरह के उपाय पहले ही कई देशों में अपनाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक तकनीकी क्षमता पहले से मौजूद है और इसे श्रीलंका में लागू किया जा सकता है।

अल-मलिकी बने प्रधानमंत्री तो इराक की मदद नहीं करेगा अमेरिका: ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी कमाल अल-मलिकी सत्ता में वापस आते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। श्री ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, ' मुझे पता चला है कि इराक नूरी अल-मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की भूल करने जा रहा है। पिछली बार मलिकी सत्ता में थे तो उनका देश गरीबी और अराजकता में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए।' श्री ट्रंप ने कहा, 'अल-मलिकी की नीतियों और विचारधाराओं के कारण, अगर वह चुने जाते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। हमारी मदद के बिना इराक के सफल, समृद्ध और स्वतंत्र होने की संभावनाएं शून्य प्रतिशत हैं। ' उल्लेखनीय है कि 2006 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले श्री अल-मलिकी को शनिवार को इराक की संसद में मुख्य शिया गुट ने सरकार बनाने के लिये मनोनीत किया था। अगले चरण में इराक के राष्ट्रपति श्री अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिये मनोनीत करेंगे, हालांकि देश में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है। इराक की संसद मंगलवार को एक राष्ट्रपति चुनने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति न बनने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित हो गयी।

वियतनाम में सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट घायल

हनोई। मध्य वियतनाम के डाक लक प्रांत में बुधवार को एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पायलट घायल हो गया। वियतनाम समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है।एजेंसी ने बताया कि आज सुबह हुए इस हादसे में पायलट पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकल गया हालांकि उसे चोटें आई है।

अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ विवाद पर 'कुछ' समाधान निकालेगा: डोनाल्ड ट्रंप

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ के मुद्दे पर 'कुछ' समाधान निकालेगा। इससे पहले इसी हफ्ते ट्रंप ने एशियाई सहयोगी देश दक्षिण कोरिया पर 'रेसिप्रोकल टैरिफ' और अन्य शुल्क बढ़ाने की धमकी दी थी। ट्रंप के इस बयान से सोल और वॉशिंगटन के बीच बातचीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच, दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री किम जंग-क्वान के अमेरिका दौरे की उम्मीद है, जहां वे अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक से बातचीत करेंगे। यह जानकारी योनहाप न्यूज एजेंसी ने दी है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'हम दक्षिण कोरिया के साथ 'कुछ' समाधान निकाल लेंगे।'

उन्होंने यह बात उस सवाल के जवाब में कही, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वे कोरिया पर टैरिफ बढ़ाएंगे। सोमवार को ट्रंप ने अचानक यह घोषणा की थी कि वे दक्षिण कोरिया पर 'पारस्परिक' टैरिफ के साथ-साथ कार, लकड़ी और दवाइयों पर लगने वाला शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर सकते हैं। ट्रंप ने इसके लिए सोल द्वारा व्यापार समझौते से जुड़े कानूनों को लागू करने में हो रही देरी को जिम्मेदार ठहराया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने योनहाप न्यूज एजेंसी को बताया कि दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में 'कोई प्रगति नहीं' की है। जबकि अमेरिका ने समझौते के तहत टैरिफ कम किए थे। जुलाई के अंत में हुए और कुछ महीनों बाद अंतिम रूप दिए गए इस समझौते के तहत, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। इसके बदले में अमेरिका ने 'पारस्परिक' टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की नई धमकी उस समय आई है, जब अमेरिका को दक्षिण कोरिया में चल रही जांचों को लेकर चिंता है। इसमें अमेरिकी कंपनी में सूचीबद्ध कूपांग इंक के खिलाफ बड़े ग्राहक डेटा लीक की जांच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों पर नियंत्रण से जुड़े कदम शामिल हैं।

बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों पर तीन और नागरिकों को जबरन गायब करने का आरोप

एजेंसी

क्वेटा। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर तीन और बलूच नागरिकों को जबरन गायब किए जाने का आरोप लगाया गया। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने कहा कि ये घटनाएं प्रांत में जबरन गुमशुदगी और कथित गैर-न्यायिक हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आई हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग 'पांक' ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए बताया कि सुराब जिले के 40 वर्षीय शिक्षक अली अहमद रेकी का 24 जनवरी को क्वेटा के गंज चौक इलाके से पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के कर्मियों ने अपहरण कर लिया। तब से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पांक के अनुसार, उसी दिन और उसी स्थान से 25 वर्षीय डॉक्टर शहजैन अहमद को भी सीटीडी ने उठा लिया। इसके अलावा, 22 वर्षीय छात्र जुनैद अहमद को 23 जनवरी को क्वेटा के क्वैरी रोड स्थित चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जबरन गायब किया गया। इस बीच, बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (बीएसओ) आजाद ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को पत्र लिखकर बलूचिस्तान में जारी कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित किया। संगठन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करते हुए इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक मंचों पर उठाने की अपील की है।

स्पेन में पांच लाख अवैध प्रवासियों को वैध दर्जा देने की योजना को मंजूरी, विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध

एजेंसी

मैड्रिड (स्पेन)। स्पेन सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब पांच लाख अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की योजना को मंजूरी दी है। आव्रजन मंत्री एलमा सैज़ ने कहा कि इस योजना के तहत नियमित किये जाने वाले प्रवासी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकेंगे। उन्होंने प्रवासन के 'सकारात्मक प्रभाव' को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नीति मानवाधिकार, एकीकरण, सामाजिक सह-अस्तित्व और आर्थिक विकास के अनुकूल है।

राष्ट्रीय प्रसारक आरटीवीई से बातचीत में सुश्री सैज़ ने कहा, 'यह केवल अनुमान हैं, लेकिन आंकड़ा लगभग पांच लाख के आसपास हो सकता है।' उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार एक ऐसे प्रवासन मॉडल को मजबूत कर रही है जो सामाजिक एकता के साथ आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देता है। यह योजना उन लोगों पर लागू होगी जो कम से कम पांच महीनों से स्पेन में रह रहे हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर

2025 से पहले अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन किया था। शर्त यह है कि आवेदकों का आपराधिक रिकॉर्ड साफ हो। यह नियमितीकरण पहले से स्पेन में रह रहे उनके बच्चों पर भी लागू होगा। आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने और जून के अंत तक जारी रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को डिक्री के माध्यम से लागू करेगी, जिसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। समाजवादी नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मुख्य दक्षिणपंथी विपक्षी दल पॉपुलर पार्टी के नेता एलबर्टो नुनेज़ फीजो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसे 'हास्यास्पद' करार देते हुए कहा कि यह कदम सार्वजनिक सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। उन्होंने लिखा, 'समाजवादी स्पेन में अवैधता को इनाम दिया जा रहा है।' उन्होंने सत्ता में आने पर आव्रजन नीति को 'जड़ से बदलने' का वादा किया। सरकार का कहना है कि यह कदम श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने, सामाजिक समावेशन बढ़ाने और लंबे समय से देश में रह रहे प्रवासियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अमेरिका के पीछे हटने से बांग्लादेश के चुनाव में अनिश्चितता : सीनेटर

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका के एक सीनियर लॉमेकर ने कहा है कि बांग्लादेश के आने वाले चुनावों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। अमेरिका की भागीदारी कम होने से लोकतांत्रिक समर्थन कमजोर हो रहा है। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसका सीधा-सीधा असर भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर पड़ता है। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष मार्क वार्नर ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में बताया कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव फ्री या निष्पक्ष होंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। वार्नर ने कहा कि जमीन पर अमेरिका का असर कम हो गया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक विकास और मानवीय सहायता बंद करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकन सॉफ्ट पावर और सहायता के खत्म होने से अब हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शॉर्ट-टर्म केयरटेकर के तौर पर उभरने के बाद हम सभी बदलाव की उम्मीद लगाए हुए थे। वह उम्मीद अब खत्म हो गई है। बांग्लादेश में युवाओं को राज करना मुश्किल लग रहा है।

वार्नर ने कहा कि मुझे पक्का नहीं पता कि बांग्लादेश की तरफ से कितना गुस्सा है, क्योंकि मेरा मानना ??है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अभी भी भारत में शरण ली है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता मुश्किल में है। हालांकि अनिश्चितता के बावजूद, मुझे बांग्लादेश में आजाद चुनाव की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश राजनीति के अलावा भी कई दबावों का सामना कर रहा है, जिसमें गरीबी, आर्थिक तनाव और पर्यावरण के जोखिम प्रमुख हैं। वार्नर ने उग्रवाद पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमने बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा को बहुत ज्यादा नहीं देखा है। अलग-अलग घटनाओं से देश की दिशा तय नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'भारत एक खतरनाक पड़ोस में रहता है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की चुनौती भारत में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री और बिजनेस से नहीं आई। दशकों तक, अमेरिका का असर विकास और लोकतंत्र बनाने की कोशिशों से भी आता रहा है। आप आर्थिक विकास और लोकतंत्र बनाने में कैसे मदद करते हैं, इस पर सॉफ्ट पावर ने एक बड़ी भूमिका निभाई।

वार्नर ने कहा कि उन कार्यक्रमों में कटौती से बांग्लादेश जैसे देशों में अमेरिका का असर कम हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि सेंसिटिव पॉलिटिकल बदलावों के दौरान आपसी जुड़ाव में दूरी आ सकती है।

उन्होंने कहा कि लगातार अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव जरूरी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को लंबे समय तक समर्थन की जरूरत है, न कि कभी-कभी ध्यान देने की।

सऊदी क्राउन प्रिंस से बोले पेजेशकियन, 'ईरान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शांति प्रक्रिया के लिए तैयार'

एजेंसी

तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान शांति स्थापित करने और लड़ाई रोकने के लिए किसी भी प्रक्रिया का स्वागत करने को तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में देश और उसके लोगों के अधिकारों की पूरी तरह से सुरक्षा करते हुए जिस भी प्रक्रिया से गुजरना हो, वह मंजूर है। सिन्हुआ ने ईरानी राष्ट्रपति के ऑफिस के एक बयान के हवाले से बताया कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में शांति और सुरक्षा पक्की करने की जरूरत पर जोर दिया। पेजेशकियन ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की धमकियों और कार्रवाइयों का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा से समझौता करना है। ईरानी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन पर यूरोप के साथ ईरान के पिछले कूटनीतिक

संबंधों में रुकावट डालने का आरोप लगाया और बातचीत के लिए अमेरिका के नजरिए को 'हम कहते हैं और आप करते हैं' जैसा बताया। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास पक्का करने के लिए मुस्लिम देशों के बीच मिलकर काम करने की अपील की। एक बयान में क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी हमले, धमकी या तनाव बढ़ाने को मंजूर नहीं मानता है। उन्होंने हमेशा शांति और सुरक्षा पक्की करने के लिए ईरान और दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग के लिए अपने देश की तैयारी जाहिर की। इसके अलावा, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की नेवी के उपकमांडर मोहम्मद अकबरजादेह ने कहा कि ईरान के पड़ोसियों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने एयरस्पेस, इलाकों या पानी के इलाके का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए न करें। सेमी-ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि अकबरजादेह ने कहा कि ईरान को होर्मोज स्ट्रेट से आसमान और समुद्र की सतह और जमीन के नीचे से लगातार डेटा मिल रहा है और ईरान तय करता है कि किस झंडे के नीचे किस जहाज और जंगी जहाज को गुजरने दिया जाए। चर्चा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक समूह इस इलाके में तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। ईरान ने किसी भी हमले पर जवाब देने की चेतावनी दी है।

अफगानिस्तान में शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करने की अपील, यूएन एजेंसियों ने जताई गहरी चिंता

एजेंसी

काबुल। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने अफगानिस्तान में बच्चों और खासकर लड़कियों की शिक्षा की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए शिक्षा के अधिकार की रक्षा की अपील की है। यूनिसेफ के अनुसार अफगानिस्तान में 10 वर्ष की उम्र के 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे एक साधारण पाठ भी पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, जो देश की शिक्षा व्यवस्था के गहरे संकट को दर्शाता है।

स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया गया कि तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से स्कूलों के बंद होने, योग्य शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं के कारण शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूनिसेफ और यूनेस्को की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 22 लाख किशोर लड़कियां शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता व गणितीय कौशल में निवेश नहीं किया गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी निरक्षरता का संकट और गहराएगा। हाल ही में काबुल सहित कई इलाकों की लड़कियों ने तालिबान से स्कूल और विश्वविद्यालय दोबारा खोलने की अपील की है, ताकि वे भी समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। उल्लेखनीय है कि तालिबान ने छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे लाखों छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

रूस ने ट्रेन पर किया हमला, पांच की मौत : ज़ेलेंस्की

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र में मंगलवार रात पैसेंजर ट्रेन पर हुए कथित रूसी ड्रोन हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा कर यह जानकारी दी।

श्री ज़ेलेंस्की ने इस हमले को 'आतंकवाद की करतूत' बताते हुए एक छोटा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगी हुई दिखायी दे रही थी। क्षेत्रीय आपातकालीन सेवाओं ने बाद में कहा कि आग बुझा दी गयी है।

श्री ज़ेलेंस्की ने 'एक्स' पर लिखा, ' ट्रेन के डिब्बे में नागरिकों को मारने का कोई सैन्य औचित्य नहीं है, और न ही हो सकता है। खासकर, ट्रेन में 200 से ज़्यादा लोग थे, और 18 लोग उस डिब्बे में थे, जिस पर रूसी ड्रोन में से एक ने हमला किया था। रूस ने हमले करने की अपनी क्षमता, आतंक फैलाने की अपनी

क्षमता में काफी वृद्धि की है। ' यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बनाने के अपने संदेश को दोहराया। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि 50 से ज़्यादा रूस के ड्रोनों के एक हमले ने काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा पर भी हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गये और दो बच्चों सहित 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गये। ड्रोन ने शहर के पावर ग्रिड को निशाना बनाया, जिस पर मॉस्को ने सर्दियों के चरम पर बिजली और हीटिंग काटने के प्रयास में बार-बार हमला किया है। साथ ही पांच अपार्टमेंट इमारतों को भी निशाना बनाया गया।यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार, ओडेसा यूक्रेनी निर्यात के लिये एक रणनीतिक केंद्र है और रूस ने इसे अक्सर निशाना बनाया है। दक्षिणी यूक्रेनी शहर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किये गये ड्रोनों में ऐसे मॉडल शामिल थे, जिन्हें हाल ही में रूस ने अपनी रेंज और मारक क्षमता में सुधार के लिए अपग्रेड किया है।

रूस ने कीव पर भी एक हमला किया, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गये। कीव क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख, मायकोला कलाशनिक ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, ' बिलोगोरोड्स्का समुदाय में, हमारे दो देशवासियों की हमले में मौत हो गयी।' यूक्रेन की पुलिस के अनुसार, इस दंपति का चार साल का बच्चा बच गया, लेकिन हमले में घायल हो गया था। तीन अन्य लोग भी घायल हुए।

सिंगापुर ने आठ विदेशी मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान की, इनमें भारत का मणिपाल भी

एजेंसी

सिंगापुर। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंगापुर मेडिकल काउंसिल ने आज आठ विदेशी मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। इनमें भारत के मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से संबद्ध कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल भी है। मंत्रालय और काउंसिल की मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई।

सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंगापुर मेडिकल काउंसिल ने कहा कि आगामी 01 फरवरी से देश से बाहर के आठ मेडिकल कालेजों (1) ऑस्ट्रेलिया एडिलेड यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हेल्थ, (2)भारत के मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, (3) आयरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, स्कूल ऑफ मेडिसिन, (4) मलेशिया यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, (5) पाकिस्तान द आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, (6) पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, (7) सिंघुआ यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ मेडिसिन और (8) सिटी सेंट जॉर्ज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, स्कूल ऑफ को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंगापुर मेडिकल काउंसिल के संयुक्त बयान में कहा गया है कि नव-अनुमोदित स्कूल सिंगापुर को बढ़ती उम्र की आबादी के बीच डॉक्टर्स की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेंगे। इन आठ मेडिकल कालेजों के साथ सिंगापुर में मान्यता प्राप्त विदेशी मेडिकल कालेजों की कुल संख्या एक फरवरी, 2025 तक 112 से बढ़कर 120 हो गई है।

मंत्रालय ने कहा कि उसने मेडिकल पंजीकरण अधिनियम 1997 की दूसरी अनुसूची में आठ मेडिकल स्कूलों को जोड़ने के लिए काउंसिल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। बयान में कहा गया है कि 2026 से जो विद्यार्थी मेडिकल डिग्री हासिल करना चाहते हैं, वे इन विदेशी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं।

बॉर्डर पैट्रोल की सीमा पर मुठभेड़, एक आदमी को लगी गोली

एजेंसी

लॉस एंजिलस। अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल से जुड़ी एक घटना में गोली लगने से एक आदमी की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने पिमा काउंटी शेरिफ विभाग के हवाले से बताया कि यह घटना अरिवाका में हुई, जो अमेरिका-मेक्सिको सीमा से लगभग 16 किमी उत्तर में है। पिमा काउंटी शेरिफ क्रिस नैनोस ने एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि संदिग्ध की पहचान एरिज़ोना के निवासी पैट्रिक गैरी श्लेगल के रूप में हुई है।यह घटना स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 7:30 बजे शुरू हुई, जब बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने एक वाहन की पहचान की। उनका मानना था कि वह एक ऐसे व्यक्ति का है, जिस पर पहले की एक घटना में मानव तस्करी का संदेह था। श्री नैनोस ने कहा, ' जब उन्होंने ट्रैफिक रोका, तो कार में बैठा अकेला ड्राइवर पैदल भागने लगा। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने पैदल उसका पीछा किया। कुछ ही देर बाद संदिग्ध ने गोलियां चलायीं और एजेंट ने जवाबी गोलीबारी की। इससे संदिग्ध को गोली लग गयी। ' स्थानीय मीडिया ने बताया कि उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और इलाज के लिए ले जाया गया। शेरिफ विभाग ने कहा कि वह एफबीआई और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

डेनमार्क-जर्मनी ने हरित ऊर्जा परियोजना समझौते पर किया हस्ताक्षर

एजेंसी

कोपेनहेगन। डेनमार्क ने जर्मनी के साथ मिलकर बोर्नहोम एनर्जी आइलैंड नामक एक प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुश्री फ्रेडरिक्सन ने हैम्बर्ग में उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में

कहा, ' यह एक सीमा पार परियोजना है जो यूरोपीय ऊर्जा बाजार को एकीकृत करती है। यह जर्मन घरों, डेनमार्क के घरों और हमारी कंपनियों को हरित विद्युत प्रदान करती है। '

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। डीपीए की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में जर्मनी और डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में बोर्नहोम द्वीप पर एक संयुक्त ऊर्जा केंद्र स्थापित एवं संचालित करने के लिए भी एक समझौता पर हस्ताक्षर किया।गौरतलब है कि इस द्वीप को बाल्टिक सागर में स्थित अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों से जर्मनी और डेनमार्क तक विद्युत पहुंचाने वाले केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना है। परियोजना के अंतर्गत दोनों देशों ने आवश्यक उपकरणों के निर्माण एवं रखरखाव की लागत साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि शिखर सम्मेलन में उपस्थित बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा मंत्रियों ने क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस उद्योग में 2030 तक लगभग 9.5 अरब यूरो का निवेश करने की योजना है।

चीन फ़िनलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए तैयार : जिनपिंग

एजेंसी

हेलसिंकी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फनलैंड के साथ मिलकर काम करने की तत्परता व्यक्त की है ताकि संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एवं अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था को दृढ़ता से कायम रखा जा सके और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना किया जा सके।श्री जिनपिंग ने ये टिप्पणियां फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मुलाकात के दौरान कीं जो चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। श्री जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन एक न्यायसंगत एवं व्यवस्थित

बहुध्रुवीय दुनिया के साथ-साथ सार्वभौमिक रूप से लाभकारी एवं समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड के साथ काम करने के लिए तैयार है।

page 1 and 8 jan 29_page 1 Mar 25 final ds.qxd 1/29/2026 12:22 AM Page 2

फसल विविधीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ईसबगोल की फसल

ईसबगोल एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। औषधीय फसलों के निर्यात में इसका प्रथम स्थान हैं। वर्तमान में हमारे देश से प्रतिवर्ष 120 करोड के मूल्य का ईसबगोल निर्यात हो रहा है। विश्व में ईसबगोल का सबसे बडा उपभोक्ता अमेरिका है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश ईरान, ईराक, अरब अमीरात, भारत, फिलीपीन्स इत्यादि हैं। भारत का स्थान ईसबगोल उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रथम है। भारत में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात ,राजस्थान ,पंजाब , हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में करीब 50 हजार हेक्टर में हो रहा हैं। म. प्र. में नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन एवं शाजापुर जिले प्रमुख है।

जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के राजौरी, उधमपुर, सांबा और जम्मू जिलों के गर्म और शुष्क क्लस्टर्स में फसल विविधीकरण के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ईसबगोल की फसल।

ईसबगोल का औषधीय उपयोग अधिक होने के कारण विश्व बाजार में इसकी मांग तेजी

से बड रही हैं। ईसबगोल के बीज पर पाएं जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद हैं जिसे ईसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता हैं। भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है।इसकी भूसी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती हैं ।इसलिए इसका उपयोग पेट की सफाई , कब्जीयत, दस्त आव पेचिस , अल्सर, बवासीर , जैसी शारीरिक बीमारियों के उपचार में आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता हैं।इसके अलावा आइसक्रीम रंग रोगन , प्रिंटिंग आदि उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता हैं ।इसकी मांग एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से करना आवश्यक हैं ।

▶▶ भूमि एवं जलवायु

ईसबगोल के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त हैं ।फसल पकते समय वर्षा व ओस का होना फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता हैं । कभी कभी फसल 100 प्रतिशत तक नष्ट हो जाती हैं। अधिक आद्रता एवं नमीयुक्त जलवायु में इसकी खेती नहीं करना चाहिए । इसके अंकुरण के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस तथा फसल की परिपक्वता के समय 30-35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हैं। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त हैं। भूमि की पी-एच मान 7-8 तक होना चाहिए।

▶▶ भूमि की तैयारी

दो बार आडी खडी जुताई एवं एक बार बखर चलावें तथा पाटा चलाकर मिटटी भुरभुरी एवं समतल कर लेवें। छोटी क्यारियां बना लें। क्यारियों की लम्बाई चैडाई खेत के ढलान एवं सिंचाई की सुविधानुसार रखें। क्यारियों की लम्बाई 8 से 12 मीटर व चैडाई 3 मीटर से अधिक रखना उचित नहीं होता हैं।

खेत में जल निकास का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। क्योंकि खेत में पानी का भराव ईसबगोल के पौधे सहन नहीं कर सकते हैं।

उन्नत जातियां -

जवाहर ईसबगोल 4 - यह प्रजाति 1996 में औषधीय एवं सुगन्धित पौध की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कैलाश नाथ काटजू उद्यानिकी महाविघालय ,मंदसौर (राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर) द्वारा म.प्र. के लिए अनुमोदित एवं जारी की गई है। इसका उत्पादन 13-15 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता है।

गुजरात ईसबगोल 2 - यह प्रजाति 1983 में अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगन्धित पौध परियोजना, आणंद, गुजरात से विकसित की गई हैं। इसका उत्पादन 9-10 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता हैं।

हरियाणा ईसबगोल 5 - यह प्रजाति अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगन्धित पौध परियोजना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा 1989 में निकाली गई हैं। इसका उत्पादन 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टर लिया जा सकता हैं।

अन्य किस्मों में गुजरात ईसबगोल 1, हरियाणा ईसबगोल - 2, निहारिका, ट्राबे सलेक्शन 1 से 10 आदि का चयन कर बुवाई की जा सकती है।

▶▶ बोआई का समय-

ईसबगोल की अगेती बोआई करने पर फसल की ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि हो जाती हैं परिणामस्वरुप फसल आडी पड जाती हैं तथा मदुरोमिल आसिता का प्रकोप बढ जाता हैं। वही पर देरी से बुवाई करने पर प्रकोप का वानस्पतिक विकास कम होता हैं और मानसून पूर्व की वर्षा से बीज झडने का अंदेशा बना रहता हैं। इसलिए किसान भाई ईसबगोल की बोआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक करते हैं तो यह अच्छा समय होता हैं। दिसम्बर माह तक बोआई करने पर उपज में भारी कमी आ जाती हैं।

बडे आकार का, रोग रहित बीज की 4 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टर की दर से उपयोग लेने पर फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता हैं। बीज दर ज्यादा होने की दशा में मदुरोमिल आसिता का प्रकोप बढ जाता हैं व उत्पादन प्रभावित हो जाता है।

ईसबगोल के बीज को मैटालैक्जिल 35 एस. डी. की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से बीजोपचार कर बुवाई करें। किसान भाई मृदा उपचार हेतु जैविक फफंदी नाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2.5 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टर की दर से अच्छी पकी हुई गोबर की खाद अथवा वर्मीकम्पोस में मिला कर नमी युक्त खेत में प्रयोग करें।

किसानों में ईसबगोल की छिटकाव पद्धति से बुवाई करना प्रचलित हैं। परंतु इस विधि से अंतःसस्य क्रियाएं करने में कठिनाई आती हैं। परिणामस्वरुप उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अतः किसान भाई ईसबगोल की बुवाई कतारों में करते हुए कतार से कतार की दूरी 30 से. मी. एवं पौधे की दूरी 5 से. मी. रखे । बुवाई करते समय बीज में महीन बालू रेत अथवा छनी हुई गोबर की खाद मिलाकर बुवाई करें जिससे वांछित बीज दर का प्रयोग हो सके। बीज की गहराई 2-3 से.मी. रखे। इससे ज्यादा गहरा बीज न बोयें । छिटकाव पद्धति से बोने पर मिट्टी में ज्यादा गहरा न मिलावें।

▶▶ खाद एवं उर्वरक

ईसबगोल का अच्छा उत्पादन हेतु अच्छी पकी हुई गोबर की खाद 15-20 टन प्रति हेक्टर डालें। 10-15 किलो नत्रजन , 40 किलो स्फुर एवं 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टर बुवाई के समय डालें। नत्रजन की 10-15 किलो प्रति हेक्टर बुवाई के 40 दिन बाद छिटकाव कर डालें।

अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई धीमी गति से करें। अंकुरण कमज़ोर होने पर दूसरी सिंचाई 5-6 दिन बाद देवें । इसके बाद प्रथम सिंचाई 30 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई 70 दिन बाद देवें। फूल एवं दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई न दें। इनमें दो से ज्यादा सिंचाई देने पर रोगों का प्रकोप बढ जाता हैं तथा उपज में कमी आ जाती हैं। पुश्पक्रम / बाली आने के बाद स्प्रिंकलर से सिचाई ना करें ।बुवाई के 20-25 दिन बाद एक बार निंदाई-गुडाई अवश्य करें । इसी समय छनाई का काम

भी कर देवें तथा पौधों की दूरी 5 से.मी. रखें । इस फसल में रासायनिक नींदा नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फुरोन की 25 ग्राम मात्रा अथवा आइसोप्रोटूरोंन की 500-750 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर बोनी के 20 दिन पर छिडकाव करें ।डाउनी मिल्ड्यू (मदुरोमिल आसिता)-मृदुल रोमिल आसिता के लक्षण पौधों में बाली (स्पाइक) निकलते समय दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पत्ती के निचले भाग में सफेद चूर्ण जैसा कवक जाल दिखाई देता हैं। बाद में पत्तियां सिकुड जाती हैं तथा पौधों की बढवार रुक जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप डंठल की लम्बाई , बीज बनना एवं बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं। रोग नियंत्रण हेतु स्वस्थ व प्रमाणित बीज बोयें , बीजोपचार करें एवं कटाई के बाद फसल अवशेषों को जला देवें। प्रथम छिडकाव रोग का प्रकोप होने पर मैटालैक्जिल .मैंकोजेब की 2-2.5 ग्राम मात्रा अथवा कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें। छिडकाव 10-15 दिन के अंतराल पर दोहराए।

मोयला - माहू का प्रकोप सामान्यतः बुवाई के 60-70 दिन की अवस्था पर होता है ।यह सुक्ष्म आकार का कीट पत्तियों, तना एवं बालियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अधिक प्रकोप होने की दषा में पूरा पौधा मधु स्त्राव से चिपचिपा हो जाता हैं तथा फसल पर क क्रिया बाधित हो जाती हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता हैं। इसकी रोकथाम हेतु आक्सी मिथाइल डेमेटान 25 प्रतिशत ई.सी. अथवा डाइमिथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. की 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में अथवा इमिडाइक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. अथवा एसिटामिप्रिड 20 प्रतिशत एस. पी. की 5 मिली/ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें एवं आव यकतानुसार छिडकाव को दोहराए ।

फसल 110-120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं , फसल पकने पर पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली एवं नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं। बालियों को हथेली में मसलने पर दाने आसानी से निकल जाते हैं। इसी अवस्था पर फसल की कटाई करें। कटाई सुबह के समय करने पर झडने की समस्या से बचा जा सकता हैं। फसल कटाई देर से न करें अन्यथा दाने झडने से उपज में बहुत कमी आ जाती हैं। मावठा आने की स्थिति में फसल कटाई 2-3 दिन जल्दी कर लेवें।

उन्नत तकनीक से खेती करने पर 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज मिल जाती हैं ।

खजूर की खेती- जलवायु, किस्में, प्रबंधन, देखभाल और पैदावार

- स्रोतः भूपेंद्र चौधरी, दैनिक जागृति

खजूर शुष्क जलवायु में उगाया जाने वाला प्राचीनतम फलदार वृक्ष है । इस वृक्ष का वानस्पतिक नाम फीनिक्स डेक्टीलीफेरा है।

यह मानव सभ्यता के सबसे पुराने खेती किये जाने वाले फलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति फारस की खाड़ी में समझी जाती है। दक्षिण इराक (मेसोपोटोमिया) में इसकी खेती ईसा से 4000 वर्ष पूर्व प्रचलित थी। मोहनजोदड़ों की खुदाई के अनुसार भारत - पाकिस्तान में भी ईसा से 2000 वर्ष पूर्व विद्यमान था। पुरातन विश्व में खजूर की व्यवसायिक खेती पूर्व में सिन्धु घाटी से दक्षिण में तुर्की-परशियन-अफगान पहाड़ियों, इराक किरकुक - हाईफा तथा समुद्री तटीय सीमा के सहारे-2 ट्यूनिशिया तक बहुतायत में की जाती थी।

इसकी व्यवसायिक खेती की शुरूआत सर्वप्रथम इराक में शुरू हुई। ईराक, सऊदी अरब, इरान, मिश्र, लिबिया, पाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनिशिया, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन विश्व के मुख्य खजूर उत्पादक देश है।

हमारे देश में सर्वप्रथम 1955 से 1962 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका व पाकिस्तान से खजूर की कुछ व्यवसायिक किस्मों के पौधे मंगवाये गये थे।

राजसथान के जैसलमेर, बारमेर, बीकानेर और जोधपुर आदि के शुष्क जलवायु वाले पश्चिमी क्षेत्र खजूर की खेती के लिए उपयुक्त पाए गये है। खजूर पर सामान्यतः अधिक तापक्रम और पाले का असर नही होने तथा लवण सहन करने की क्षमता के कारण राज्य का काफी बड़ा क्षेत्र खजूर की खेती के अन्तर्गत प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता हैं। ऐसे क्षेत्र जो बहुत अधिक लवणीय हैं अथवा जहा जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था नही है अथवा सिंचाई हेतु लवणीय जल ही उपलब्ध है जो अन्य फसलों के लिए उपयुक्त नही वहा पर भी इसकी खेती की जा सकती है।

जम्मू कश्मीर के बागबानी विभाग ने भी जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास आरंभ किए हैं।

खजूर की खेती मुख्यतः शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र जहां लम्बी गर्म हवायें व गर्मी, अत्यधिक कम वर्षा व बहुत कम आर्द्रता होती है, में की जाती है। अरब देशें में मान्यता है कि अधिक बढ़वार और उपज के लिए खजूर के पेड़ों के सिर तपती आगनुमा गर्मी में तथा जड़ें पानी में रहनी चाहिए। खजूर के फल जुलाई- -अगस्त में पकते हैं। इस समय भी वर्षा और अधिक वातावरणीय नमी होने पर फल समुचित रुप से नही पक पाते तथा सड़कर नष्ट हो जाते हैं। भारत के अधिकांश भागों में इस समय मानसून सक्रिय हो जाते है।

पश्चिमी राजसथान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर आदी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानसून की वर्षा प्रायः कम होती है। खजूर की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में औसतन वार्षिक वर्षा जैसलमेर में 100-250 मिलीमीटर, बीकानेर में 304 मिलीमीटर, बारमेर में 330 मिलीमीटर तथा जोधपुर में 366 मिलीमीटर और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 322 मिलीमीटर तक होती है। फल पकते समय हल्की वर्षा भी शुरु की अवस्था में भारी वर्षा से अधिक हानीकारक होती है।

खजूर के फलों एवं फलों के समुचित विकास के लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती हैं। यह गर्मीयों में 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दीयों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक के तापमान को भी सह लेता है।

डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी वानस्पतिक बढ़वार के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है। खजूर में पुष्पन और फलों के पकने हेतु क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस व 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त पाया गया है। देश के खजूर उत्पादन

योग्य क्षेत्रों को लगभग 4 भागों में बाटा जा सकता है। जो इस प्रकार है, जैसे-

1. जैसलमेर तथा बारमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के अधिक शुष्क पश्चिमी भाग।
2. कच्छ का समुद्री तटीय क्षेत्र तथा सौराष्ट्र का कुछ भाग।
3. जोधपुर, बीकानेर और बारमेर के पूर्वा भाग और नागौर, चुरु व श्रीगंगानगर जिलोंके पश्चिमी भाग।
4. अबोहर, सिरसा, श्रीगंगानगर, चुरु जिलों के पूर्वी भाग और सीकर का पश्चिमी भाग।

खजूर की खेती ऐसी लवणीय मृदायें जिनका पीएच मान 8 से 9 तक हो सफलतापूर्वक की जा सकती हैं। खजूर का वृक्ष भूमि में 3 से 4 प्रतिशत तक क्षारीयता सहन कर सकता है, यद्यपि जड़ों की सामान्य कार्य शक्ति के लिए एक प्रतिशत से अधिक क्षारीयता नही होनी चाहिए। भूमि में अधिक पीएच लवण और क्षार पौधों की वानस्पतिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं। भूमि में 2 मीटर गहराई तक कंकड़ अथवा पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत नही होनी चाहिए। अच्छी जल धारण क्षमता और जल निकास की समुचित व्यवस्था वाली मिट्टी खजूर की खेती के लिए उत्तम रहती है।

▶▶ खजूर की खेती के लिए किस्में

भारत में खजूर की किस्में अरब देशों से लाई गई हैं। वैसे तो अरब देशों में खजूर की एक हजार से भी अधिक किस्में हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही व्यावसायिक रुप से पैदा की जाती है, जैसे- इराक की हलावी, खदरावी, सायर, बरही और जाहिदी, उत्तर अफ्रीकी देशों की डेग्लेटनूर, मैडजूल, घार्स तथा पाकिस्तान की बेगम जंगी एवं ढक्की मुख्य हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1955-1962 के दौरान खजूर की कुछ किस्में इन देशों से लाई गई तथा उनका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के फल अनुसंधान केन्द्र, अबोहर में मूल्यांकन किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत देश के चार केन्द्रों (अबोहर, बीकानेर, जोधपुर, मुन्द्रा (कच्छ) पर अनुसंधान प्रगति पर है।

▶▶ खजूर का प्रवर्धन

खजूर के पौधें में नर और मादा फूल अलग-अलग पौधों पर आते हैं। एक बीजपत्री होने के कारण खजूर के पौधें कायिक प्रवर्धन के अन्य तरीकों, जैसे कलम बांधना (ग्राफ्टिंग), चश्मा चढाना (बडिंग), गुटी व कलम विधियों द्वारा तैयार नही किये जा सकते। इसका प्रसारण बीज, सकर्स (अंतःभूस्तारी) व टिश्यूकल्चर तीन विधियों से किया जाता है, जैसे-

बीज द्वारा- खजूर के एकलिंगी (डायोसिस) होने से बीज से तैयार किये पौधों में नर और मादा का अनुपात 50:50 रहने की सम्भावना रहती है। इस विधि से तैयार पौधों में फूल व फल आना शुरु होने के बाद ही उनके नर मादा होने का पता चल पाता है। बीज से निकले नर पौधे सिर्फ परागकण के ही होते हैं, इन पर फल नही बनतें है। वहीं इसके मादा पौधे मातृ पौधे से भिन्न गुणों वाले होते है। ऐसे पौधो में फल देरी से आने शुरु होते है और उपज में भी असमानता रहती है इस कारण खजूर के पौधों का प्रर्वधन अच्छी गुणवत्ता वाले मादा मातृ पेड़ों से सकर्स (अंतःभूस्तारी) द्वारा किया जाता है।

सकर्स द्वारा- सकर्स (अंतःभूस्तारी) द्वारा तैयार पौधे मातृ पौधे से गुणवत्ता में समान होते है। ये पूर्ण विकसित पेड़ों की जड़ों के पास तने के भाग की कलिकाओं से निकलते है। सकर्स द्वारा तैयार पौधे बीज से तैयार पौधों की तुलना में 2-3 वर्ष पहले फलत में आते है। खजूर के एक पेड़ से उसके पूरे जीवन काल में 15 से 20 सकर्स प्राप्त होते है। ये पौधें के रोपण के बाद शुरु के 10 से 15 वर्ष की उम्र तक पैदा होते हैं। पौधें लगाने के लगभग 4 वर्ष बाद से पौधे से किस्म के आधार पर 3 से 5 सकर्स प्रतिवर्ष अलग किए जा सकते है। पेड़ की आयु लगभग 10 वर्ष होने के पश्चात सकर्स पैदा होना लगभग बन्द हो जाते है। इसी कारण अच्छी किस्मों के सकर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने में काफी कठिनाई आती है।

सकर्स द्वारा प्रवर्धन करने पर सकर्स का भार 8-10 किलो ग्राम तथा इनकी जड़े पूर्ण विकसित होनी चाहिए। सकर्स में जड़े पूर्ण विकसित करने के लिए पेड़ों के तने के पास मिट्टी चढ़ाई जाती हैं और उसको पानी लगाकर नम रखा जाता है। मातृ पेड़ से सकर्स को काफी सावधानी से अलग किया जाना चाहिए। पेड़ से अलग करने के एक-दो दिन पहले खेत में पानी लगाना चाहिए।

अलग करने से पहले सकर्स की पत्तियों को उसके शीर्ष भाग से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर से काट दें तथा पत्तियों की बची हुई डण्डियों को मिलाकर रस्सी से बांध दें। इसके पश्चात् उसके पास की मिट्टी को हटा कर उनको मातृ पेड़ के साथ उनके जोड़ स्थान से कुंट और हथोड़े की सहायता से काट कर अलग कर दें। तत्तपश्चात सकर्स को जड़ समेत अलग निकाल लें तथा दूसरे खेत में रोपाई की तैयारी कर लगा देना चाहिए और तुरन्त सिंचाई देनी चाहिए।

टिश्यू कल्चर द्वारा- खजूर के पौधों पर सकर्स पर्याप्त मात्रा में नही बनने से वृहद स्तर पर प्रसारण के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के पौधे नही मिल पाते है। इस समस्या का समाधान टिश्यू कल्चर तकनीक है। टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने कई लाभ हैं, जैसे-

1. कुछ पौधों से ही बड़ी संख्या में पौधे तैयार किये जा सकते है।
2. पौधों की आनुवंशिकता गुणवत्ता मातृ वृक्ष के समान रहती है।
3. वृहद स्तर पर पौधे तैयार किये जा सकते है।

4. वर्ष भर पौधे तैयार किये जा सकते हैं, मौसम का फर्क नही पड़ता।

विश्वस्तर पर टिश्यू कल्चर तकनीक से खजूर के पौधे तैयार करने के प्रयास किये जा रहे है, लेकिन इनमें से कुछ ही प्रयोगशालाओं को इसमें सफलता मिल पायी है। अभी लगभग 6-8 प्रयोगशालायें यह कार्य कर रही हैं इनमें से इग्लेंड में चार, फ्रांस में दो, इजरायल, नामिबिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में एक - एक हैं। अधिकांश प्रयोगशालाओं द्वारा बरही तथा मेडजूल किस्मों के पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किये जा रहे है। खजूर के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे प्रथमिक हार्डनिंग अवस्था पर प्रयोगशाला से निकाल कर खेत में रोपण के लिए तैयार किये जाते है। प्राथमिक हार्डनिंग अवस्था के मापदण्ड व प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे-

1. दो से तीन पत्तियां आने पर।
2. पौधों की ऊँचाई 10 से 15 सेन्टीमीटर होने पर।
3. लगभग 5 सेन्टीमीटर आकार की जड़े विकसित होने पर।
4. तने का आधार प्याज के बल्ब के आकार का होने पर।

खजूर की पौध लगाने का समय

जूर का वृक्ष कम से कम 40 से 50 वर्षों तक फलत में रहता है, इसलिए इसके पौधों को उचित फासले पर लगाना बहुत आवश्यक हैं। प्रायः कतार से कतार तथा पौधे से पौधें के बीच 8 मीटर का फासला रखा जाता है। इससे पौधें की समुचित फैलाव होता है और पौधों के बीच में की जाने वाली कृषि क्रियाएं सुगमतापूर्वक की जा सकती है। इस प्रकार एक हैक्टर में लगभग 156 पौधे लगाये जा सकते हैं। खजूर एकलिंगी पेड़ होने से नर व मादा पुष्पन अलग-अलग पेड़ों पर आते है। इसलिए खेत में परागण हेतु नर पेड़ों का होना आवश्यक है। एक नर पेड़ से 10-15 मादा पेड़ों के लिए पर्याप्त परागकण उपलब्ध हो सकते है

पौधें लगाने के लिए 1 मीटर लम्बे, 1 मीटर चौड़ें और 1 मीटर गहरे गड्ढे पौध लगाने के एक माह पहले खोद लेने चाहिए। गड्ढों में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी तथा 20 किलो ग्राम सड़ी हुयी गोबर की खाद, 1.60 किलो ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 250 ग्राम क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण या फैनवलरेट 0.4 प्रतिशत चूर्ण मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। पौधे लगाने से पहले गड्ढों में पानी देना चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाये। पौधों को लगाते समय थैली को पैंदें से काट लें। इसके बाद थैली में नीचे आधे ऊपर तक चीरा (कट) लगा दे। थैली के नीचे हाथ रखकर थैली को पकड़कर गड्ढे के बीच में रख कर चारों तरफ मिट्टी से दबा दें। पौधे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौधे के बल्ब का केवल 3/4 हिस्सा मिट्टी के अन्दर रहे तथा क्राउन मिट्टी में नही दबे। इसके बाद पौधों की अच्छी तरह सिंचाई कर दे।

- संकलन- चंद्र मोहन शर्मा